

मौसम अधिकतम तापमान **38.0°C**
न्यूनतम तापमान **30.3°C**



राजधानी पटना व आसपास के क्षेत्रों में आज भी बारिश के आसार

हवा	प्रतिशत
हां	75%
नहीं	15%
कह नहीं सकते	10%

बाजार

सोना 1,53,000



चांदी 2,55,000



सेंसेक्स 78,079.96



निफ्टी 24,395.85



संक्षिप्त खबरें
लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री
व अन्य ने दी अहिल्याबाई
होल्कर को श्रद्धांजलि

हैं दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केन्द्रीय गृह एवं सहकारितामंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने गुजरात को अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि पर उद्देश्यश्रृंखला अर्पित की। पुण्यतिथि ने लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ वटर्जी को भी याद किया। उन्होंने वटर्जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बिरला ने एसएनएल लिखा, लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुण्यतिथि हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अहिल्याबाई ने अपने संसदनकाल में किसानों, कारीगरों, व्यापारियों और आम नागरिकों की हलाकों को प्राथमिकता दी और साथ ही महलों में व्यापार, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। उनका शासन जन-कल्याण, सुशासन और जन-सेवा का एकप्रेरणादायक उदाहरण है। धर्म और संस्कृति के संरक्षक के साथ-साथ, उन्होंने देश के कई प्रमुख स्थलों पर मंदिरों, घाटों, कुओं, बावड़ियों और विश्राम-गृहों के निर्माण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों का व्यापक प्रभाव आज भी भारत की संस्कृतिक विरासत में दिखाई देता है। लोकमाता के महान योगदान और विरासत के सम्मान में, संसद पुस्तकालय भवन के प्रवेश में स्थापित उनकी यह प्रतिमा केवल एक महान नायिका की स्मृति ही नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, जन-कल्याण की भावना और जन-सेवा के आदर्शों का प्रतीक है। सोमनाथ वटर्जी का सार्वजनिक जीवन उनकी गहरी विद्याई संझझ, संसदीय परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि लोकमाता ने मंदिरों की जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण, तीर्थस्थलों के विकास तथा सांस्कृतिक पर्यटन के संरक्षण और पुनर्स्थापना में अद्वितीय योगदान दिया। महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देकर अहिल्याबाई होल्कर ने महिलाओं को शक्ति बनाया तथा जन-कल्याण, न्याय तथा सुशासन का आदर्श स्थापित किया।

देश की सान्

प्रातः किरण, एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां देश के प्रतिष्ठित कलाकारों 2024 और 2025 के लिए 'संगीत अकादमी फेलोशिप तथा संगीत अकादमी पुरस्कार प्रदान किए और भारतीय परंपरा के वाहक ये कला की सामूहिक स्मृति के संरक्षक और की कल्पना के सृजक हैं। श्रीमती मुर्मू कि सम्मानित किए गए कलाकारों में का ऐसा सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत

जिसमें इस देश की मिट्टी की क
जुड़े हैं, ऐसा मान्यचित्त जिस
भरी इस धरती के नृत्य और
और सूर्ययों से विकसित हुई
और बोलियों की यादें समाई
कहा कि भारत की संस्कृति
हुई है। अलग-अलग खान-
नृत्य और संगीत, प्रकृति से प्रे
हुए चिड़ियों से, कल-कल व
पड़-पतों से, बादलों से, ना
लेकर कलाकार अपने नृत्य
प्रदर्शित करते हैं। विविधता

ए और गीत
विविधता से
व समाए हैं
नी भाषाओं
राष्ट्रपति ने
ओं से जुड़ी
वेषभूषा,
हैं, चहकते
झरनों से,
से प्रेरणा
संगीत को
एकता का



यह संगम हमारी शक्तियों में से एक कि सभी विभिन्न परंपरा की महत्त्व कहा, ह्व हमारी क पुस्तक जीवित गुरु बदलते दौर में हम पु विलुप्त होने क कला विधाओं का रचना जरूरी है व लिए विशेष प्रयास कहा यह अच्छी

आओं की सबसे बड़ी अकादमी में कार्यक्रम का वरिष्ठ कलाकारों की तैयार करें। राष्ट्रपति और समस्त प्रकृति को सज्जता है। लं जीवन का साथ रहने के रूपों में सहज रूप से

उद्देश्य से ह्यकला-दीक्षाह मायोजन कर रही है। उन्होंने ने से कहा कि वे अगली पीढ़ी के लिए योजनापूर्वक प्रयास ने कहा कि कला के संस्कार जीवन को समृद्ध करने के लिए सहज प्रशिक्षण संरचना माना और जनजातीय कलाओं में भाविक उल्लास और प्रकृति विवाद दिखाई देता है। इन कला की स्मृति और सामूहिक चेतना रक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला के अभाव में युवा पीढ़ी की हमारे संस्कृति हैं। उन केन्द्र किया भारत को ल

पाएँ भारत की सांस्कृतिक पहचान त महत्वपूर्ण आधार हैं। राष्ट्रपति राणो पावे वाले कलाकारों को बधाई दे रहा कि भारतीय परंपरा के विश्वनाकार देश की सामूहिक स्मृति के और भविष्य की कल्पना के सुझाव कहा कि संगीत नाटक अकादमी की साँट पावर का एक महत्वपूर्ण जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त अकादमी आने वाले समय में भी सांस्कृतिक ऊर्जा से समूचे विश्वन्वत करती रहेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर पर 2-लेन स्लिप रोड पुल का किया लोकार्पण

प्रातः किरण, एजेंसी

की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ दैनिक यात्रियों की आवाजाही को और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान ऐसी आधारभूत संरचना विकसित करने पर है, जिसका सीधा और व्यापक लाभ आम नागरिकों को मिले। सड़क, टेलिवर्क को मजबूत करना, यातायात के दबाव को कम करना और दिल्ली

के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बेहतर आवागमन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कोडडोल में यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित और विकसित दिल्ली की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कोडडोल के विभिन्न हिस्सों में सड़क, फ्लाइटटर्क के विकास के साथ-साथ सुनिश्चित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मध्यमंजी ने कहा

विपक्ष पर बरसीं कंगना रनौत, कहा- खराब कर रखा है संसद का माहौल

प्रातः किरण, एजेंसी



मिडिया संग बातचीत में विपक्ष पर
 चर्चा करते हुए कहा कि उनके पास
 चर्चा में भाग लेने की हिम्मत ही नहीं
 है, तो वे जवाब क्या सुनेंगे। उन्होंने
 कहा, जवाब सुनने की हिम्मत होनी
 चाहिए, जो उनके पास नहीं है। चर्चा
 में भाग लेने की हिम्मत उनको ही नहीं
 है। उन्होंने कहा कि मुझ ही नहीं है।
 देश में जो प्रश्नचक्र कर रहा है।
 कांग्रेस की नींव कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी
 गई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी
 जनता के दिलों से खेलती चली आई
 है और अभी भी यही कर रही है।
 उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी जनता के
 साथ थोड़ा धीमी कर रही है। जनता ने
 उन्हें चर्चा में भाग लेने, उनका दुख-
 दर्द सुनने के लिए चाहा है।

राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित मानूसन सत्र में महज 39 प्रतिशत उत्पादकता रही

प्रातः किरण, एजेंसी



भी नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले व्यवधानों का असररक्षण के लिए अलग-अलग लोगों के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं पर पड़ता है। इसलिए, सत्य की सदस्यों को संसदीय आचरण के अत्यधिक मानकों को बनाए रखने और सदस्य संस्था की गरिमा तथा पवित्रता की रक्षा करना का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक के नुकसान के बावजूद सदन ने अपने मूल विधानों को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि यदि सदस्य न्यायिक रूप से सदन की कार्यवाही के बारे में भाग लेते, अपने महत्वपूर्ण सुझावों और सार्थक विचार-विमर्शों में शामिल होते तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती। सत्र के अंतिम दिन, सदस्य आपत्ति की अनुमति से शून्यकाल और प्रश्नकाल को स्थगित करके

खायान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के अन्तर्गत प्रस्तावित विधेयक पर चर्चा हुई। खान मंत्री जी किष्किण सिंह जी के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में 128 विधेयकों पर विचार किया और 128 विधेयकों या वापस किया गया। इनमें में प्रस्तावित खान हार्द्व मातर के अपमान या अपमान के गान को दंडनीय बनाने संबंधी प्रस्तावना वाला राष्ट्रीय गौरव विधेयक, खान नवगण (संशोधन) विधेयक, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के प्राधान संबंधी संवैधानिक न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 तथा केरल का नाम बदलकर केरल करने के प्राधान वाला होकरल नाम परिवर्तन विधेयक, 2026 विधेयक शामिल हैं। इस दौरान लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद सदन ने 29 जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक, 2026 को मंजुरी दी थी।

स्वतंत्रता दिवस समारोह: कड़ी सुरक्षा के बीच लाल किला पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल

प्रातः किरण, एजेंसी

नाई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता की यात्रियों को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास फुल ड्रेस रिवर्सल का आयोजन किया गया। इस रिवर्सल का आयोजन गुरुवार की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मजबूती सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के कड़े बरोबर के बीच किया गया। स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के मौके पर लाल किले की प्रवेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। साथ ही, कई तरह के प्रतिबंध लगाने जाएं जा सकते हैं। राष्ट्रीय के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मोदी के मुताबिक, आज रिवर्सल का आयोजन किया गया है। ऐसे मौकों पर शाहरदा काफ़ी सेवेदनशील इलाकों पर नज़र जाता है। सीमा की दृष्टि से देखे, तो हमारे जिले से कुल सात सीमाएं हैं और उत्तर प्रदेश हमसे सीमा पर है। लिहाजा इन इलाकों से ट्रैफिक रात 10 बजे से पूरी तरह बंद रहेगी। उनके मुताबिक, वैसे तो पूरे जिले में पहले से ही चौकियां हैं। लेकिन, हमने अपने जिले में कुछ अस्थायी चौकियां भी बनाई हैं। हमने यह सुनिश्चक किया है कि हर प्रकन की आपातकालीन स्थिति में रेषापॉन्स हिकल, पेडो

हकल अपने-अपने इलाकों में हर कार को आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। रिश्त-पुलिस अधिकारी ने बताया ६ लाल किला परिसर के पीछे, गुला नदी का ख़ादर वाला इलाका रक्षा व्यवस्था काफ़ी दुर्बल कर गई है। उन्होंने कहा कि हम इन इलाकों में 15 अगस्त तक ट्रेडिंग रस्ते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस जोन-2 (तिरुक्कल पुलिस आयुक्त (एसपी) नेशनल कुमार गुला ने कहा कि राष्ट्रीय जघाना में दिल्ली में रात 10 बजे तक तबन्ध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में व्यवसायिक वाहनों की पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमने उन प्रदेश और हरियाणा जुड़े अधिकारियों से भी संपर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि इन इलाकों में किसी भी प्रकार व्यवसायिक वाहनों को आने से रोकें, ताकि भीड़ पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक के पार्क कई डायवर्जन प्वाइंट भी बनाए रहे हैं।

हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा का आआपा पर हमला, केजरीवाल से मांगा जवाब

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद युधायशु त्रिवेदी ने पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी (आपा) और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड और पंजाब के मुद्दों पर पुनः रुहने वाले अरविंद केजरीवाल अब बताएँ कि जब अदालत में उनकी सरकार का झूठ सामने आ गया है, तो क्या वह अपनी सरकार से इस्तीफा दिलवाएंगे? उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप भी लगाया। भाजपा सांसद ने कहा कि पंजाब विधानसभा में झूठ, संसद में बवाल और अदालत द्वारा उठाए गए सवाल वह साफ दिखाते हैं कि छात्र हितों की बात करने वालों की तथाकथित नैतिकता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। गुप्तावर को मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद सुधाशु आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे झारखंड और पंजाब से जुड़े मुद्दों पर पुनः चुरा रहे, जबकि काँग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन मामलों पर कथित तौर पर ध्यान नहीं दिया। त्रिवेदी ने संसद में हुए हंगामे और न्यायपालिका द्वारा उठाए गए सवालों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर संसदीयक मर्यादाओं और नैतिकता के दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के हितों का सबसे बड़ा पैरोकार बताते हैं, उनकी राजनीतिक और संवैधानिक नैतिकता अब सवालों के घेरे में है। मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। छात्र हितों से उनका कोई सरोकार नहीं है।

राष्ट्रपति के दौरेन प्रतिनिधिमंडल ने केन-बेतवा नदी....
राष्ट्रपति परियोजना के प्रभावितों से मिले राहुल गांधी



असर से भी उन्हें अवगत कराया। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जे केन-बेवला परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में आदिवासी, किसान और स्थानीय ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभावित लोगों की प्रमुख चिंताओं

विस्थापन, मुआवजे में देरी, पुनर्वास की व्यवस्था और वन अधिकारों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले 5 अगस्त को राहुल गांधी ने लोकसभा में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ा

सवाल भी उठाय़ा था। हाहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अंडल सिंह (मामलों ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय से परियोजना से प्रभावित परिवारों व निवासियों के विवरण और विवरण कर रहे आदिवासियों समुदायों की शिकायतों पर सरकार की ओर से कोई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी थी। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उड्डे ने लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय को केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण विस्थापन से संबंधित कई अप्यावेदन मिले हैं। इन अप्यावेदन की जांच के बाद उई मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित जिला प्रशासन को जांच तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। केन्द्र ने कहा है कि वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जिम्मेवारी है। उल्लेखनीय है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना देश की पहली नदी

गोडो परिचयजना है। इसके तहत वध्र प्रदेश की केन नदी पानी न्ध आर प्रेश की बेववा नदी तक ह्चाया जाना है। परिचयजना में के के अलावा नहरों और सुरीो न निर्माण शामिल है। परिचयजना से दिल्खड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। परिचयजना की अनुमानित लागत 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार के अनुसार नसे बुल्लखड क्षेत्र में 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और करीब 62 लाख लोगों को पेयजल का लाभ मिलेगा। लाकि, परिचयजना से प्रभावित लोगों का कहना है कि विकास के वेत्रोह के बजाय उनकी चिंता उचित नर्वस, पारदर्शी मुआवजे और वन वं जमीन से जुड़ अधिकारों को है।

प्रातः किरण, एजेंसी

करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी इस मामले को गंभीरता से लेंगे। नड्डा ने कहा, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। राज्यसभा के सभापति

जी.पी. राधाकृष्णन ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि छुआछूत केसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, हम सभी इस घटना की निंदा करते हैं। हम सभी समान हैं और केसी के शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है। सरकार इस मामले की जांच कराए और दोषियों को सजा मिले।

संक्षिप्त

समाचार

मुनस्यारी में बनेंगे दो ट्रैकिंग रूट, बड़ेगा साहसिक पर्यटन

पिथौरागढ़, एजेंसी। पर्यटन नगरी मुनस्यारी में जल्द ही दो नए ट्रैकिंग रूट अस्तित्व में आएंगे। इससे क्षेत्र के साथ ही जिले के साहसिक पर्यटन को नई पहचान और उड़ान मिलेगी। नए ट्रैकिंग रूट बनाने के लिए 81 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है जिससे पर्यटन कारोबार भी बड़ेगा। मुनस्यारी क्षेत्र में मर्तोली पीक और बुर्फूथार प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। यहां तक पहुंचने के लिए बदहाल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। अब इन दोनों पर्यटक स्थलों तक पहुंच आसान बनाने की कवायद शुरू हुई है। मुनस्यारी क्षेत्र साहसिक पर्यटन का केंद्र है। हर साल देश-विदेश से ट्रैकर क्षेत्र के ग्लेशियरों और चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं। राम देवी मंदिर से मर्तोली पीक अंशेर बुर्फू गांव से बुर्फूथार तक ट्रैकिंग रूट बनेंगे जिससे ट्रैकरों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन कारोबार को भी गति मिलेगी। मुनस्यारी क्षेत्र में मिलम, नामिक और रामल ग्लेशियर ट्रैकरों की पहली पसंद हैं। मिलम ग्लेशियर को कुमाऊं के सबसे बड़े ग्लेशियर के रूप में भी पहचान मिली है जो गौरी गंगा का उद्गम स्थल भी है। वहीं नामिक ग्लेशियर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत परिवेश के लिए जाना जाता है जो ट्रैकर्स के बीच लोकप्रिय है। रामल ग्लेशियर तन देवी और पंचाचूली की पहाड़ियों के करीब स्थित एक बेहद खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग रूट है। इन ग्लेशियर में ट्रैकिंग के लिए हर साल बड़ी संख्या में ट्रैकर पहुंचते हैं। अब दो नए ट्रैकिंग रूट विकसित होने से पर्यटकों की संख्या में और उछाल आने की उम्मीद है।

मास्को में कई भारतीय युवाओं के होनेकी आशंका जो लौटना चाहते हैं स्वदेश

पिथौरागढ़, एजेंसी। रोजगार का झंसा देकर रूस के मास्को भेजे गए दोनों भाइयों चिमस्यानौला निवासी आनंद सिंह काकी और भूपेंद्र सिंह काकी की सकुशल वापसी हुई है। दोनों ने पिथौरागढ़ पहुंचकर आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि जिस काम का वादा कर उन्हे मास्को भेजा गया वह नहीं मिला। वापस लौटने की इच्छा जताई तो उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया गया। बमुरिकल दोनों भाई भारतीय दूतावास पहुंचे तो वहां तैनात महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी और वहां की पुलिस ने उनकी काफी मदद की। सीएम के हस्तक्षेप के बाद वह अपने वतन लौट सके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें झंसे में लेकर झूठा वादा करते हुए मास्को भेजा था वह पूर्व में 15 हजार से अधिक भारतीय युवाओं को वहां भेज चुकी है। ऐसे में साफ है कि अब भी मास्को में कई भारतीय युवा उन्हीं की तरह दिक्कत झेल रहे हैं जो स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। संवाद आनंद सिंह और भूपेंद्र सिंह ने संवाद न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि उनके साथ धोखा होने का आभास होते ही उन्होंने किसी तरह भारतीय दूतावास पहुंचने का लक्ष्य तय कर लिया था। हुआ भी ऐसा ही। किसी तरह बचते-बचाते दोनों भारतीय दूतावास पहुंचे तो उन्हें मदद मिल गई। उन्होंने कहा कि यदि दूतावास नहीं पहुंचते और पहले की स्वदेश लौटने की इच्छा जताते तो उनका पासपोर्ट और वीजा छीन लिया जाता। ऐसे में उनकी स्वदेश वापसी मुश्किल हो जाती।

शिक्षा के साथ अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी भी जरूरी

रूड़की, एजेंसी। सनातन धर्म प्रकाश चंद कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवप्रवेशित छात्राओं के स्वागत, मार्गदर्शन और महाविद्यालयी जीवन से परिचय कराने के मकसद से तीन दिवसीय दीक्षार्थ कार्यक्रम का बुधवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम 12 से 14 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सौरभ भूषण शर्मा ने शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को जरूरी बताया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि सौरभ भूषण शर्मा, सचिव प्रबंध समिति एवं प्रदेश संयोजक, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, भाजपा उत्तराखंड ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश उच्च शिक्षा के साथ व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास और जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ा रही हैं। छात्राएं बड़े सपने देखें, निरंतर मेहनत करें और अपने माता-पिता व संस्थान का नाम रोशन करें। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के एक पेड़ मां के नाम, हर घर तिरंगा और नशा मुक्त भारत अभियानों की जानकारी देते हुए छात्राओं को इनकी शपथ दिलाई। प्रत्येक छात्रा को मां के नाम पौधा भेंट किया गया जबकि हर घर तिरंगा के तहत तिरगे वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रार्चार्थ डॉ. अनुपमा गर्ग ने की। वरिष्ठ प्रवक्ता प्रोफेसर आदित्य आनंद ने बताया कि इन गतिविधियों का मकसद छात्राओं को महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आत्मीय रूप से जोड़ते हुए उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सहयोगी भावना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना है। आईक्यूएस्सी कोऑर्डिनेटर डॉ. भारती शर्मा ने बताया कि अभियानों से करीब 22 ग्रामों से जुड़ी छात्राओं को जोड़ा गया है। डॉ. कामना जैन ने बताया कि कार्यक्रम में एंटी-रैगिंग जागरूकता, मंटर-मेंटी परिचय, खेल, आई हैव ए ड्रीम सहित विभिन्न गतिविधियां होंगी। कार्यक्रम में शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रही।

छह साल की मासूम छत से गिरी, एयर एंबुलेंस से पहुंचाया जिला अस्पताल

पिथौरागढ़, एजेंसी। मुनस्यारी के मर्तोली गांव निवासी छह साल की मासूम छत से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रशासन से गुहार के बाद मासूम को एयर एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां भी मासूम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हॉयर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक छह साल की लक्षिता अपने घर की छत पर खेल रही थी। इसी दौरान वह असंतुलित होकर आंगन में गिर गई। उसके सिर और शरीर में गंभीर चोट आई। आनन फानन में परिजन उसे लेकर मुनस्यारी सीपचसी पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए एयर एंबुलेंस की मांग की। प्रशासन ने बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा।

बस है या मालगाड़ी! 30 की क्षमता वाली बस में दूसे 168 यात्री, अब हो गया बड़ा एक्शन



रुद्रपुर/किच्छा, एजेंसी। यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर क्षमता से कई गुना अधिक सवारियां भरकर दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने-जाने वाली निजी बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है. किच्छा में 50 यात्रियों की क्षमता वाली बस में करीब 110 यात्री मिलने के बाद 1.07 लाख रुपए का चालान किया गया, जबकि लालपुर में 30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 103 और दूसरी बस में 168 यात्री मिलने से हड़कंप मच गया. निजी बसों में क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को दूँधकर ले जाने के मामले ने परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर संचालित हो रही ओवरलोड बसों के खिलाफ उधम सिंह नगर में परिवहन विभाग ने लगातार तीन दिनों से अभियान तेज कर दिया है. किच्छा और लालपुर क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान बसों में निर्धारित क्षमता से कई गुना अधिक यात्री मिले. कहीं 50 की क्षमता वाली बस में करीब 110 यात्री मिले तो कहीं 30 स्लीपर की क्षमता वाली बस में 168 यात्री सवार पाए गए. इन कार्रवाईयों में विभाग ने लाखों रुपए के चालान करने के साथ बसों को सीज करने और परमिट व

चालक के लाइसेंस पर कार्रवाई शुरू की है. **50 की क्षमता, 110 यात्री:** 7 अगस्त शनिवार रात टनकपुर से लुधियाना जा रही जगदंबा ट्रेवल्स की निजी बस को किच्छा में सूरजमल कॉलेज के पास परिवहन विभाग की टीम ने रोककर जांच की. बस की निर्धारित क्षमता करीब 50 यात्रियों की थी, लेकिन जांच के दौरान करीब 110 यात्री सवार मिले. यात्रियों के मुताबिक भीड़ इतनी अधिक थी कि एक सीट पर 7 से 8 लोगों तक को बैठाकर सफर कराया जा रहा था. एआरटीओ हल्द्वानी जितेंद्र कुमार ने बस का 1 लाख 7 हजार 500 रुपए का चालान किया. साथ ही बस का परमिट निरस्त करने

और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई. कार्रवाई के बाद यात्रियों को रात में रुद्रपुर बस स्टेशन लाया गया. यात्रियों ने बताया कि, शुरुआत में एक सीट पर चार-पांच लोग बैठाए गए थे, लेकिन रास्ते में लगातार सवारियां चढ़ती गईं और बस में पैर रखने तक की जगह नहीं बची. महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रियों ने संचालकों पर मनमाना किराया वसूलने और विरोध करने पर कथित तौर पर रास्ते में उतारने की धमकी देने का आरोप लगाया. **30 स्लीपर में 168 यात्री मिलने से हड़कंप:** इसी दौरान लालपुर में परिवहन

विभाग की टीम ने लखीमपुर खीरी से पंजाब जा रही एक बस को 9 अगस्त देर रात करीब एक बजे जांच के लिए रोका. बस को महज 30 स्लीपर और एक सीट की क्षमता के लिए पास किया गया था, लेकिन जांच में 138 वयस्क और 30 बच्चों समेत कुल 168 यात्री मिले संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय के निर्देश और एआरटीओ नवीन सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. प्रभारी सुतेया सचल दल के परिवहन कर अधिकारी जितेंद्र सिंगवान ने बस की जांच की. इस दौरान ओवरलोडिंग के साथ बिना टैक्स और बिना परमिट संचालन समेत अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं. विभाग ने बस का चालान कर उसे रोडवेज स्टेशन रुद्रपुर में सीज कर दिया.

दूसरी बस में 30 स्लीपर की क्षमता, 103 यात्री: 10 अगस्त लालपुर टोल के पास ही पंजाब जा रही एक अन्य यूपी नंबर की बस में महज 30 स्लीपर की क्षमता के बावजूद 103 यात्री मिले. बस के अंदर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर परिवहन अधिकारियों के भी होश उड़ गए. विभाग ने ओवरलोडिंग के साथ परमिट और फिटनेस संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए बस सीज कर करीब 1.34 लाख रुपए का

चालान किया. **यात्रियों को वैकल्पिक बसों से भेजा:** कार्रवाई के बाद सबसे बड़ी चुनौती बसों में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की थी. परिवहन निगम की ओर से वैकल्पिक बसों की व्यवस्था कर यात्रियों को रुद्रपुर से उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया. सहायक महाप्रबंधक मधुसूदन मिश्रा ने यात्रियों के लिए वाहन उपलब्ध कराने में सहयोग किया. **लगातार कार्रवाई, फिर भी बड़ा सवाल:** तीन दिनों से लगातार हो रही कार्रवाई ने परिवहन विभाग की सक्रियता तो दिखाई है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है. आखिर दूसरे राज्यों से चलने वाली निजी बसें क्षमता से कई गुना अधिक यात्रियों को लेकर उत्तराखंड की सीमा तक कैसे पहुंच रही हैं क्या इन बसों की रास्ते में नियमित जांच नहीं होती यदि बसों में 30 स्लीपर की जगह 103 या 168 यात्री भरे जा रहे हैं तो यह स्थिति केवल एक स्थान पर नहीं बनती होगी. परिवहन विभाग का कहना है कि ओवरलोड बसों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि क्षमता से अधिक सवारियां ले जाने वाली बसों में यात्रा न करें.

आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों पुनर्नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

नैनीताल, एजेंसी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की वरिष्ठता विवाद को लेकर दायर याचिकाओं पर एक अहम निर्णय सुनाया है. न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें विभाग द्वारा जारी 2019 की अंतिम वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2009 में हुई शुरुआती चयन प्रक्रिया और उसकी मेरिट सूची रद्द होने के बाद, फार्मासिस्टों की वरिष्ठता का निर्धारण 7 नवंबर 2012 को जारी हुए नए नियुक्ति आदेश और उसकी मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा. यह पूरा मामला वर्ष 2009 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक द्वारा निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ा है. उस समय चयन समिति ने बैक-पेपर या पूरक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अलग श्रेणी में रखते हुए योग्यता सूची में नीचे कर दिया था. इसके खिलाफ प्रभावित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 2012 में एकलपीठ ने पुरानी चयन सूची को निरस्त करते हुए नियमानुसार नई सूची तैयार करने के आदेश दिए थे. बाद में विशेष अपील में भी इस फैसले को बरकरार रखा गया था. शासन



ने फिर 2012 में नए सिरे से नियुक्तियां दीं, लेकिन विभाग ने 2019 में जारी वरिष्ठता सूची में पुराने 2009 के बैच के कर्मचारियों को पिछली तिथि से वरिष्ठता का लाभ दे दिया, जिसे ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया था. पुरानी वरिष्ठता का दावा कर रहे अभ्यर्थियों (जैसे कुमारी पूनम भट्ट व अन्य) ने ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उनका तर्क था कि वे 2009 से बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार काम कर रहे हैं. उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ

भी मिला है. हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि 2009 की चयन प्रक्रिया पूरी तरह रद्द हो चुकी थी. किसी भी पक्ष ने बैक-डेटेड (पिछली तिथि से) नियुक्ति का कोई कानूनी आदेश प्राप्त नहीं किया था, इसलिए 7 नवंबर 2012 को जारी नया आदेश ही वास्तविक मौलिक नियुक्ति माना जाएगा. अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश को विधि सम्मत मानते हुए सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दीं.

केवाईसी और पर्ची जनेट की दिक्कत में उलझे गैस उपभोक्ता रूड़की, एजेंसी। गैस एजेंसियों में बुधवार को केवाईसी और गैस बुकिंग की पर्ची जनेरेट नहीं होने से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंडियन ऑयल के सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खामी के कारण शहर की विभिन्न एजेंसियों पर दिनभर काम प्रभावित रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता एजेंसियों पर पहुंच गए थे लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी अधिकारश लोगों का काम नहीं हो सका। दीपाली, छवि, प्रभात, देवभूमि, सावित्री और एकता समेत कई गैस एजेंसियों पर सुबह नौ बजे से भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक सर्वर सामान्य नहीं हो पाया जिससे केवाईसी और गैस बुकिंग की पर्ची जनेरेट करने का काम बाधित रहा। उपभोक्ताओं ने बताया कि जरूरी कार्यों के लिए समय निकालकर एजेंसी पहुंचे थे लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उन्हें बिना काम कराए लौटना पड़ा। उपभोक्ताओं के अनुसार शहरभर की एजेंसियों में यही स्थिति रही और करीब 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए। लियाकत, तेयब, सोनू, हरीश बिष्ट, हेमलता बहुगुणा, पिंकी शर्मा, सुष्टि, ध्रुव और रुद्राक्ष सहित कई लोगों ने समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। एजेंसी संचालकों ने बताया कि सर्वर रूक-रूक कर काम कर रहा था जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा हुई। केवाईसी कराने के लिए बुधवार को कई उपभोक्ता गैस एजेंसी कार्यालय पहुंचे। केवाईसी प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क भी जमा करना पड़ा। कई लोगों ने शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया लेकिन भुगतान के मैसेज तत्काल एजेंसी संचालकों के पास नहीं पहुंचे। इससे उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच भुगतान हुआ या नहीं इसको लेकर बहस की स्थिति बन गई। उपभोक्ताओं का कहना था कि उनके खाते से रकम कट चुकी है जबकि एजेंसी संचालकों को भुगतान प्राप्त होने की जानकारी नहीं मिल रही थी। कुछ उपभोक्ताओं के भुगतान के मैसेज कुछ देर इंतजार करने के बाद एजेंसी संचालकों को प्राप्त हो गए। इसके बाद उनकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी की गई। भुगतान संबंधी तकनीकी दिक्कत के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

चंबा में श्रीदेव सुमन का स्मारक बदहाल

शराब की बोतलें और कूड़े से पटा परिसर

टिहरी, एजेंसी। चंबा में स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद श्रीदेव सुमन की स्मारक बदहाल स्थिति में है. स्मारक परिसर में जहां साफ-सफाई और सम्मान का वातावरण होना चाहिए था, वहां शराब की खाली बोतलें, गुटखे के पाउच और कूड़ा-कचरा पड़ा दिखाई दे रहा है. जिससे श्रीदेव सुमन के सम्मान के साथ जनभावनाओं को ठेस पहुंच रहा है. ऐसे में स्मारक के रखरखाव और साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है.

राजशाही के चंगुल से टिहरी की प्रजा को किया था आजाद: बता दें कि श्रीदेव सुमन ने अपने जीवन का बलिदान टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक अधिकारों एवं जनहित की आवाज उठाते हुए दिया था. ऐसे महानायक की स्मृति में बनाया गया स्मारक आज खुद बदहाली का शिकार नजर आ रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्मारक परिसर में नियमित साफ-सफाई और रखरखाव का अभाव है.

परिसर में असामाजिक तत्व शराब की खाली बोतलें, गुटखे के पाउच और अन्य कूड़ा-कचरा फेंक रहे हैं.

श्रीदेव सुमन के स्मारक पर गंदगी: लोगों का कहना है कि जिस स्थान से आने वाली पीढ़ियों को श्रीदेव सुमन के संघर्ष, त्याग और बलिदान की प्रेरणा मिलनी चाहिए, अगर



वही स्थान गंदगी और अव्यवस्था का शिकार रहेगा, तो यह शहीद के सम्मान के साथ जनभावनाओं के साथ भी अन्याय है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से स्मारक की तत्काल सफाई कराने, नियमित

रखरखाव की व्यवस्था करने एवं परिसर में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है. 'टिहरी जिले की पहचान श्रीदेव सुमन की वजह से है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके स्मारक के आसपास बेहद गंदगी है. नगर पालिका की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. जहां पुस्तकालय बनाया जाना था, वहां पर कूड़ा कचरा फैला है. अगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा. ' - अमर शहीद श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के उन महान सपूतों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना जनता के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया. उनका जीवन और बलिदान आज भी प्रदेश की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. चंबा शहर में उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए स्मारक बनाया गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि स्मारक के रखरखाव की ओर ज़िम्मेदार विभाग और स्थानीय प्रशासन का पर्याप्त ध्यान नहीं है.

पिथौरागढ़ में सातू-आदू पर्व के लिए सजने लगे मुखौटे

पिथौरागढ़, एजेंसी। सीमांत जिले में शिव-पार्वती को समर्पित सातू-आदू पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए मुखौटे सजने लगे हैं। यह पर्व मुखौटा संस्कृति का भी वाहक है जो पूरे प्रदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सीमांत जिले में नगर से लेकर करखों, गांवों तक सातू-आदू पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार 19 को सातू और 20 अगस्त को आदू पर्व मनाया जाएगा इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर के साथ ही कनालीछीना, सतगढ़, सिरौली, पनखोली, डुंगरी, बस्तड़ी, अस्कोट सहित अन्य क्षेत्रों में युवा इसकी तैयारी में जुट गए हैं। यह पर्व गौरा-महेश्वर यानि शिव-पार्वती को समर्पित है। सातू पर्व पर विशेष घास सी से गौरा जबकि दूसरे दिन आदू पर्व को महेश्वर की प्रतिमा स्थापित कर इनकी पूजा-अर्चना होगी। इस पर्व की विशेष पहचान मुखौटा संस्कृति भी है। पर्व पर



मुखौटों के जरिए बैलों की जोड़ी, हिरन चीतल, महाकाली आदि का प्रदर्शन

किया जाता है। सतगढ़, कनालीछीना सहित अन्य क्षेत्रों में पर्व के लिए मुखौटे

सजने लगे हैं। युवा इन मुखौटों पर रंग चढ़ाकर इन्हें सँवारने के साथ इस प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने में जुटे हैं। पिथौरागढ़। जिले के सतगढ़, कनालीछीना, सिरौली सहित अन्य हिस्सों में झोड़ा-चांचरी का गायन शुरू हो गया है। सातू-आदू पर्व पर टुलखेल के माध्यम से भगवान शिव, मां गौरा, भगवान कृष्ण सहित अन्य देवी-देवताओं की आराधना भी की जाती है। महिलाएं और पुरुष झोड़ा-चांचरी का गायन कर अपनी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। संवाद सातू-आदू पर्व पर बिरुड़ से मां गौरा के पूजन की परंपरा है। बिरुड़ पांच या सात अनाजों का मेल होता है इसमें सबसे प्रमुख गुरुश हैं जो विशेष अनाज है। गुरुश के साथ मटर, गेहूं सहित पांच या सात अनाजों का मिश्रण भिगोया जाता है। सातू पर्व पर इसे नौले-धारों के पवित्र जल से धोया जाता है। इसी बिरुड़ से मां

गौरा का पूजन होता है। पूजन के बाद बिरुड़ को पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। संवाद नगर से लगी ग्राम सभा फोती स्थित त्यौदर बाबा मंदिर में आठ दिवसीय संगीतमय शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ जारी है। कथा सुनने के लिए दूर-दराज के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। कथा के दौरान पुरोहित सागर पुनेठा और आचार्य भुवन बगौली ने सुबह पूजा-अर्चना संपन्न कराई। दोपहर बाद गायन कर अपनी लोक कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने हैं। संवाद सातू-आदू पर्व पर बिरुड़ से मां गौरा के पूजन की परंपरा है। बिरुड़ पांच या सात अनाजों का मेल होता है इसमें सबसे प्रमुख गुरुश हैं जो विशेष अनाज है। गुरुश के साथ मटर, गेहूं सहित पांच या सात अनाजों का मिश्रण भिगोया जाता है। सातू पर्व पर इसे नौले-धारों के पवित्र जल से धोया जाता है। इसी बिरुड़ से मां

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE"), (AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBIICDR REGULATIONS")



TECHNOCRAFT VENTURES LIMITED

(To be listed on the main board of BSE and NSE)

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the name "Technocraft Construction Private Limited" under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated October 21, 1998, issued by the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana. Thereafter, the name of our Company was changed from "Technocraft Construction Private Limited" to "Technocraft Ventures Private Limited" pursuant to a board resolution dated January 08, 2024, and a special resolution passed by our shareholders dated January 10, 2024, and a fresh certificate of incorporation dated February 09, 2024, was issued pursuant to change of name, by the Registrar of Companies, Delhi. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Board of Directors dated February 16, 2024, and a special resolution passed by our shareholders on March 13, 2024. Consequently, the name of our Company was changed to "Technocraft Ventures Limited", and a fresh certificate of incorporation was issued to our company by the Registrar of Companies, Central Processing Centre, on June 11, 2024. For further details, kindly refer "Our History and Certain Corporate Matters - Brief History of our Company" beginning on page 328 of the Prospectus filed with ROC.

Corporate Identity Number: U70101DL1998PLC096763 **Registered Office:** S 553/54, Ground Floor, School Block, Shakarpur, New Delhi-110092, India; **Corporate Office:** B-137, Sector-2 Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, India; **Contact Person:** Shefali Kesarwani, Company Secretary and Compliance Officer, **Tel.:** +91 9211252228; **E-mail:** compliance@technocraftventures.com; **Website:** www.technocraftventures.com

PROMOTERS OF OUR COMPANY: SANJAY TYAGI, REKHA TYAGI, KARTIKEY TYAGI, KARTIKEY CONSTRUCTIONS (PARTNERSHIP FIRM) AND SANJAY TYAGI HUF

Our Company has filed the Prospectus with the RoC, dated August 12, 2026 and the Equity Shares are proposed to be listed on the main board of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and the trading will commence on Friday, August 14, 2026.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 11,881,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF TECHNOCRAFT VENTURES LIMITED ("OUR COMPANY") OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 212 PER EQUITY SHARE ("OFFER PRICE") (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 202 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO ₹ 2,518.77 MILLION (THE "OFFER"). THE OFFER COMPRISES OF A FRESH ISSUE OF 9,505,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AGGREGATING ₹ 2015.06 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 2,376,000 EQUITY SHARES BY KARTIKEY CONSTRUCTIONS (PARTNERSHIP FIRM) (THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND REFERRED TO AS, THE "SELLING SHAREHOLDER" (THE "OFFER FOR SALE"). THE OFFER CONSTITUTING 30% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL."

PRICE BAND: ₹ 200 TO ₹ 212 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH.
THE FLOOR PRICE IS 20 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES AND
THE CAP PRICE IS 21.20 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

RISK TO INVESTORS

For details, kindly refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page 33 of the Prospectus.

A. Risk to Investors:

- Business Concentration Risk:** We have generated 85.44%, 80.22% and 90.91% of our revenue from operations for the financial year ended on March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024, respectively, from Water & Wastewater Infrastructure work. We are a multidisciplinary public infrastructure development company engaged in the execution of turnkey Engineering, Procurement and Construction ("EPC") contracts. We operate across various infrastructure segments, including Water & Wastewater Infrastructure such as Water Supply Scheme Projects ("WSSPs"), Sewerage Networks, Sewerage Treatment Plants ("STPs"), Wastewater Treatment Plants ("WWTPs"), Transmission mains, Reservoirs, Trenchless & Micro tunnelling Works, Roads and Highways work, Electrical Transmission work, Urban Infrastructure which includes sector-level planning and execution of residential building projects and Operation and Maintenance ("O&M") of public utilities.

The business segment wise bifurcation of revenue for the financial year ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024 are as below:

(₹ in million)

Particulars	For the Financial Year ended					
	March 31, 2026		March 31, 2025		March 31, 2024	
	Amount	% of revenue from operations	Amount	% of revenue from operations	Amount	% of revenue from operations
Sale of Services						
Water & Wastewater Infrastructure work	2,947.64	85.44	2,242.61	80.22	2,055.48	90.91
Roads and Highways work	444.04	12.87	20.38	0.73	-	0.00
Urban Infrastructure work	-	-	248.38	8.88	-	0.00
Electrical Transmission work	-	-	210.30	7.52	-	0.00
Operation & Maintenance work	57.71	1.67	24.50	0.88	13.79	0.61
Other Operating Revenues						
Sale of Material	0.57	0.02	49.47	1.77	191.75	8.48
Total	3,449.96	100.00	2,795.64	100.00	2,261.02	100.00

As certified by Rishi Kapoor & Company, Chartered Accountants pursuant to their certificate dated July 10, 2026 vide UDIN: 26455362TEEDWY3049.

- Revenue Concentration Risk:** A substantial portion of our revenues is derived from contracts awarded by Central and State Governments, local authorities under Government-led schemes such as the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation ("AMRUT"), Jal Jeevan Mission ("JJM"), Namami Gange and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ("PMGSY"). Our order book is therefore highly dependent on Government budgetary allocations and policy priorities. Any reduction or reallocation in public spending, delay in issuance of tenders, change in pre-qualification norms, or cancellation of awarded projects could materially reduce our pipeline of opportunities.

The table below sets forth our revenue from Government & Government authorities and from Private clients for the financial years ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024 indicated:

(₹ in million)

Particulars	For the financial year ended		
	March 31, 2026	March 31, 2025	March 31, 2024
Revenue from Government	3,449.39	2,274.52	1,741.50
% of Revenue from Operations	99.98	81.36	77.02
Revenue from Private Sector	0.57	521.12	519.52
% of Revenue from Operations	0.02	18.64	22.98
Total	3,449.96	2,795.64	2,261.02

As certified by Rishi Kapoor & Company, Chartered Accountants pursuant to their certificate dated July 10, 2026 vide UDIN: 26455362MFNQNB9135.

Our Company may face execution risks, including delays in approvals, resource mobilisation, site challenges, adverse weather, land acquisition issues, labour shortages, and supply chain disruptions in future. Our Company may not be able to successfully bid for and/or procure government orders in the future. Any inability to secure such orders, or a reduction in the number or value of government contracts awarded to our Company, could adversely affect our revenue, financial condition and results of operations.

- Geographical Concentration Risk:** Our Company's project portfolio is geographically concentrated, with a significant presence in Uttar Pradesh and Rajasthan. Our Company's geographic concentration in Uttar Pradesh and Rajasthan exposes it to risks such as regional slowdowns in infrastructure spending, changes in state policies or political conditions, limited geographic diversification, challenges in competing for large national projects due to a regional market perception, and constraints on efficiently expanding and clustering projects across other states.

Following are the state wise bifurcation of revenue for the financial year ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024:

(₹ in million)

Sr. No.	Name of the States	For the Financial Year ended March 31,					
		2026		2025		2024	
		Revenue from Operations	% of Revenue from Operations	Revenue from Operations	% of Revenue from Operations	Revenue from Operations	% of Revenue from Operations
1.	Uttar Pradesh	881.00	25.53	756.39	27.06	1,382.72	61.15
2.	Rajasthan	2,175.25	63.05	1,665.42	59.58	730.64	32.31
3.	Delhi	355.21	10.30	163.53	5.85	147.66	6.54
4.	Uttarakhand	-	-	210.30	7.52	-	-
5.	Madhya Pradesh	38.50	1.12	-	-	-	-
	Total	3,449.96	100.00	2,795.64	100.00	2,261.02	100.00

As certified by Rishi Kapoor & Company, Chartered Accountants pursuant to their certificate dated July 10, 2026 vide UDIN: 26455362LGVDP3135.

- Ability to qualify and bid for Government Tenders:** Our Company relies on competitive government tenders to secure infrastructure projects across sectors such as water, wastewater, power, roads, microtunneling and urban infrastructure. Its ability to win contracts depends on meeting technical and financial eligibility criteria, which may change over time. Delays, cancellations, or unsuccessful bids can result in wasted bid preparation costs and reduced business opportunities. Even after winning a contract, delays in project awards or commencement can lead to underutilized labour and equipment, increasing costs and reducing profitability.

The table below sets forth details of the cumulative bids submitted by us and the corresponding conversion metrics for the period ended July 15, 2026 and for the financial years ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024 indicated:

-

Particulars	Solo bid by the Company	Bid as a Lead Partner	Bid as a Joint Venture Partner
Bids submitted	56	9	6
Less: Cancelled/ Awaited/ Pending Result	20	1	3
Net bids submitted	36	8	3
Awarded	13	6	0
Successful Conversion of Bids (in %)	36.11	75.00	0.00

- Financial Risks:** A substantial portion of our revenues is derived from contracts awarded by Central and State Governments. The execution of large infrastructure projects involves high working capital requirements, and any shortfall or delay in the availability of working capital may adversely affect our project execution, business and financial condition, cash flows and results of operations. Further, our business requires significant working capital investment, which constitutes trade receivables and inventories together form a substantial part of our non-cash current assets, constituting 79.50%, 72.93% and 74.59% of total non-cash current assets as of March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024, respectively.

Risk related to Working Capital Requirement Risk

Our operations across infrastructure segments, including water and wastewater projects, roads, electrical networks, and civil construction are inherently working capital intensive due to significant upfront expenses in procurement, mobilization, and project execution. As per our restated consolidated financial Information, our working capital requirements for the financial year ended March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024 amounted to ₹ 1,338.16 million, ₹ 1,400.09 million and ₹ 1,280.66 million, respectively. Further, our working capital requirements for Financial Year 2027 are estimated at ₹ 2,909.29 million out of which an amount of ₹ 1,500.00 million will be funded out of the Net Proceeds from issue of fresh equity shares in financial year 2027, whereas the balance, if any, would be arranged from our internal accruals and/or borrowings. For details of our working capital requirements and estimation, kindly refer "Objects of the Offer" beginning on page 136 of the Prospectus.

Risk related to Trade Receivables & Trade Payables

As majority of our revenue is generated through the government tenders so our Company's trade receivables constitute only receivables from Governments:

(₹ in million)

Particulars	For the financial year ended		
	March 31, 2026	March 31, 2025	March 31, 2024
Trade Receivables	1,179.76	581.84	1,001.83
Revenue from operations	3,449.96	2,795.64	2,261.02
Trade Receivables as % of revenue from operations	34.20	20.81	44.31

The increase in our trade receivables as at March 31, 2026 was primarily attributable to the timing of billing during Fiscal 2026, with approximately 40% of our revenue from operations of ₹ 3,449.96 million being billed during the fourth quarter while approximately 56% was billed during the third and fourth quarters combined. Consequently, a substantial portion of the invoices remained outstanding as at the fiscal year-end, resulting in trade receivables of ₹ 1,179.76 million, of which ₹ 1,131.08 million were outstanding for less than six months.

Risk related to Contingent Liabilities:

Our contingent liabilities and commitments (as per Ind AS 37), derived from the Restated Consolidated Financial Information is ₹ 99.79 million and the following bank guarantees have been provided against the works:

(₹ in million)

GUARANTEES			
Particulars	As at		
	March 31, 2026	March 31, 2025	March 31, 2024
A) Bank Guarantees	1,680.33	1,113.16	792.27
Total	1,680.33	1,113.16	792.27

For further details, kindly refer "Restated Consolidated Financial Information - Annexure 46 - Contingent Liabilities and Commitments" beginning on page 438 of the Prospectus.

If a significant portion of these liabilities materialize, it could have an effect on our results of operations and financial condition. Further, there can be no assurance that we will not incur similar or increased levels of contingent liabilities in the future.

- Risk of seasonality of operations of the Company:** Our business operations may be affected by seasonal factors which may restrict our ability to carry on activities related to our construction projects, laying of water pipes and fully utilize our resources.

The following factors may restrict our ability:

- > Heavy or sustained rainfalls
- > Flood
- > Cyclones or
- > Other extreme weather conditions

The above could result in delays or disruptions to our operations during the critical periods of our projects and cause severe damages to our premises and equipment's. In particular, the monsoon season may adversely affect our ability to carry on activities related to our projects and efficiently utilize our resources, resulting in a Slowdown in construction projects. This may lead to delays in project execution and consequently defer the recognition of revenue and profits to subsequent quarters. Adverse seasonal developments may also necessitate the evacuation of personnel, suspension or curtailment of operations, damage to construction sites or delays in the delivery of materials. Such fluctuations may adversely affect our revenues, cash flows, results of operations and financial conditions.

- Orders in our order book may be delayed, truncated, modified, or cancelled, and may not translate into confirmed orders**

As on July 15, 2026, our Order Book includes 14 EPC projects across water & wastewater treatment infrastructure work and roads and highways work with an aggregate unexecuted contract value of ₹13,054.45 million and 5 Operations and Maintenance (O&M) projects aggregating ₹ 152.87 million. Our Order Book represents the unexecuted value of ongoing and newly awarded contracts. It is compiled based on internal estimates and is unaudited. The methodology used by our Company may differ from industry practices and should not be construed as a guaranteed measure of future revenue or profitability. The realization of income from our Order Book is subject to various factors including but not limited to project approvals, site conditions, contractual timelines and changes in project scope or specifications by the client.

(₹ in million)

Sr. No.	Particulars	FY 2025-26	FY 2024-25	FY 2023-24
1.	Opening balance of Order Book	7,688.20	7,528.80	3,243.20
2.	Add: New orders awarded during the year	8,156.60	2,752.00	5,729.10
3.	Less: Sales booked*	3,449.96	2,798.40	2,262.10
4.	Add/less: Variation/Reduction	(35.87)	205.80	818.60
5.	Closing Order Book	12,358.97	7,688.20	7,528.80

*Revenue from operations as per audited standalone statement of profit & loss.

...continued from previous page.

8. **Outstanding Legal Proceeding:** There are proceedings pending at different levels of adjudication before various courts, enquiry officers and appellate forums involving our Company, Directors, Promoters, Key Managerial Personnel (KMPs) and Senior Managerial Personnel (SMPs). Such proceedings could divert management’s time, attention and consume financial resources in their defense. Further, an adverse judgment in some of these proceedings could have an adverse impact on our business, financial condition, and result of operations
9. **Regulatory Risk:** The company is unable to trace certain historical corporate records and RoC filings, and some statutory filings contain incomplete or inaccurate disclosures that have not been revised. Under the circumstances elaborated above, our Company cannot assure you that the filings were made in a timely manner, or the information gathered through other available documents of our Company are correct. Also, our Company may not be in a position to attend to and / or respond appropriately to any legal matters pertaining to such period and relating to such documents which have been lost and to that extent the same may adversely affect our business operations.
10. The average cost of acquisition of Equity Shares for the Promoter Selling Shareholder is ₹ 2.50 and offer price at upper end of the price band is ₹ 212.
11. Weighted average cost of acquisition (WACA) of Equity Shares by our Promoters (including the Promoter Selling Shareholder):

Particulars	Number of Equity Shares of face value of ₹ 10 each	WACA of Equity Shares of face value of ₹ 10 per Equity Share acquired in last 18 months (in ₹)	WACA of Equity Shares of face value of ₹10 per Equity Share acquired in last 1 year (in ₹)	WACA of Equity Shares of face value of ₹ 10 per Equity Share acquired in last 3 years (in ₹)
Sanjay Tyagi	1,212,000	0.10	Nil	0.10
Rekha Tyagi	395,200	Nil	Nil	Nil
Kartikey Tyagi	600,000	Nil	Nil	Nil
Sanjay Tyagi HUF	2,114,200	Nil	Nil	Nil
Kartikey Constructions^	24,990,000	Nil	Nil	Nil

Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For detail kindly refer **“Risk Factors”** beginning on page 33 of the Prospectus.

BID / OFFER PROGRAMME	ANCHOR INVESTOR BID OPENED & CLOSED ON : THURSDAY, AUGUST 06, 2026
	BID / OFFER OPENED ON : FRIDAY, AUGUST 07, 2026
	BID / OFFER CLOSED ON : TUESDAY, AUGUST 11, 2026

The Offer was made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR, read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer was made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50% of the Net Offer was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (“**QIBs**”) (such portion referred to as “**QIB Portion**”) provided that our Company, in consultation with the BRLM, allocated 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the “**Anchor Investor Portion**”), of which 40% of the Anchor Investor Portion was reserved for allocation in the following manner: (i) 33.33% for domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% was reserved for Life Insurance Companies and Pension Funds, subject to valid Bids having been received from domestic Mutual Fund, Life Insurance Companies and Pension Funds at or above the price at which Equity Shares was allocated to the Anchor Investors (“**Anchor Investor Allocation Price**”), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Any under-subscription in the reserved category specified in clause (ii) above, could be allocated to domestic Mutual Fund. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares were made added to the Net QIB Portion. (other than the Anchor Investor Portion). Further, 5% of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds subject to valid Bids having been received at or above the Offer Price, and the remainder of the QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids having been received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in Mutual Fund Portion were added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer was made available for allocation to NRIs (out of which: (a) one-third of the portion available to NRIs was reserved for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹0.20 million and up to ₹ 1.00 million ; and two-thirds of the Non-Institutional Category was reserved for allocation to Bidders with Bid size of more than ₹ 1.00 million and under-subscription in either of these two sub- categories of Non-Institutional Category could be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Category). Further, not less than 35% of the Net Offer was made available for allocation to NRIs, in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids having been received from them at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount (“ASBA”) process by providing details of their respective Bank Accounts and UPI ID (in case of UPI bidders using the UPI Mechanism), in which case the corresponding Bid Amounts was blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank(s) as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through ASBA process. For details, kindly refer “*Offer Procedure*” beginning on page 576 of the Prospectus.

The bidding for Anchor Investor opened and closed on Thursday, August 06, 2026. The Company received 04 applications from 04 Anchor Investors for 35,64,050 Equity Shares. The Anchor Investor Offer Price was finalized at ₹ 212 per Equity Share. A total of 35,63,810 Equity Shares were allocated under the Anchor Investor Portion aggregating to ₹ 755.53 million.

The Offer received 13,60,671 applications for 32,70,82,350 Equity Shares resulting in 27.53 times subscription as disclosed in the Prospectus. The details of the applications received in the Offer from Retail Individual Bidders, Non-Institutional Bidders, QIBs and Anchor Investors are as under (before technical rejections):

Sr. No.	Category	No. of Applications applied	No. of Equity Shares	Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
A	Qualified Institutional Bidders -Anchor	4	35,64,050	35,63,810	1.00	75,55,78,600
B	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchor)	51	10,01,23,100	23,76,690	42.13	21,22,60,97,200
C	Non Institutional Investors -1	39,585	4,03,79,850	5,94,050	67.97	8,56,05,28,200
D	Non Institutional Investors -2	14,691	7,63,53,130	11,88,100	64.26	16,18,68,63,560
E	Retail Individual Investors	13,06,340	10,66,62,220	41,58,350	25.65	22,61,23,90,640
	Total	13,60,671	32,70,82,350	1,18,81,000	27.53	69,34,14,58,200

*This includes 5,529 applications for 3,87,100 Equity Shares from Retail Individual Investor which were not in book but excludes bids (UPI Mandates & SCSBs cancelled) not accepted by investor.

Final Demand

Assumary of the final demand as per NSE and BSE as on the Bid/Offer Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Total	Cumulative % of Total
1	200	1,93,340	0.06	1,93,340	0.06
2	201	15,470	0.00	2,08,810	0.06
3	202	15,190	0.00	2,24,000	0.06
4	203	3,850	0.00	2,27,850	0.07
5	204	4,270	0.00	2,32,120	0.07
6	205	44,240	0.01	2,76,360	0.08
7	206	6,090	0.00	2,82,450	0.08
8	207	13,790	0.00	2,96,240	0.09
9	208	18,060	0.01	3,14,300	0.09
10	209	5,390	0.00	3,19,690	0.09
11	210	47,740	0.01	3,67,430	0.11
12	211	20,370	0.01	3,87,800	0.11
13	212	23,82,66,490	68.94	23,86,54,290	69.06
	CUT OFF	10,69,39,840	30.94	34,55,94,130	100.00
		34,55,94,130	100.00		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE on August 12, 2026.

A. Allotment to Retail Individual Bidders (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Bidders, who have bid at cut-off or at the Offer Price of ₹212 per Equity, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 24.91 times. The total number of Equity Shares Allotted in Retail Individual Bidders category is 41,58,350 Equity Shares to 59,405 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	70	11,92,788	94.08	8,34,95,160	80.61	70	32:683	39,12,020
2	140	41,377	3.26	57,92,780	5.59	70	44:939	1,35,730
3	210	11,981	0.94	25,16,010	2.43	70	14:299	39,270
4	280	5,160	0.41	14,44,800	1.39	70	31:661	16,940
5	350	4,216	0.33	14,75,600	1.42	70	41:873	13,790
6	420	1,715	0.14	7,20,300	0.7	70	16:343	5,600
7	490	2,134	0.17	10,45,660	1.01	70	44:939	7,000
8	560	588	0.05	3,29,280	0.32	70	1:21	1,960
9	630	376	0.03	2,36,880	0.23	70	9:188	1,260
10	700	1,360	0.11	9,52,000	0.92	70	4:85	4,480
11	770	300	0.02	2,31,000	0.22	70	7:150	980
12	840	326	0.03	2,73,840	0.26	70	15:326	1,050
13	910	5,570	0.44	50,68,700	4.89	70	44:939	18,270
	TOTAL	12,67,891	100.00	10,40,00,000	100.00			41,58,350

B. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹0.20 million and upto ₹1.00 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹ 0.20 million and upto ₹ 1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹ 212 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 66.96 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 5,94,050 Equity Shares to 606 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	980	36,779	94.24	3,60,43,420	90.61	980	12:773	5,59,580
2	1,050	763	1.95	8,01,150	2.01	980	12:763	11,760
3	1,120	181	0.46	2,02,720	0.51	980	3:181	2,940
4	1,190	116	0.30	1,38,040	0.35	980	1:58	1,960
5	1,260	59	0.15	74,340	0.19	980	1:59	980
6	1,330	41	0.11	54,530	0.14	980	1:41	980
7	1,400	191	0.49	2,67,400	0.67	980	3:191	2,940

As certified by the Rishi Kapoor & Company, Chartered Accountant pursuant to their certificate dated July 10, 2026.
^Also the Promoter Selling Shareholder.
Note: Weighted average cost of acquisition of all equity shares during last one year, 18 months and three years has been calculated after considering the shares allotted by way of bonus issue and gift.

12. Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted by our Promoters (including Promoter Selling Shareholder) and members of the Promoter Group in last 1 year, 18 months and 3 years immediately preceding from the date of Prospectus is as follows:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition of Equity Shares (in ₹)	Cap price is 1.74 times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price- Highest Price (in ₹)
Last 1 year	Nil	Nil	Nil
Last 18 months	121.76	1.74	121.76-121.76
Last 3 years	121.76	1.74	121.76-121.76

As certified by the Rishi Kapoor & Company, Chartered Accountant pursuant to their certificate dated July 10, 2026.
Note: Weighted average cost of acquisition of all equity shares during last one year, 18 months and three years has been calculated without considering the shares allotted by way of bonus issue and gift.

13. Weighted Average Return on Net Worth for last three financial years is 24.55%.
14. Weighted average cost of acquisition for all the shares transacted in the last one year, 18 months and 3 years preceding the date of the Prospectus is given in point 11 above.
15. The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2026 for our Company at the upper end of the Price band is 14.73 times as compared to the average industry peer group PE ratio of 24.73 times.
16. The BRLM associated with the Offer i.e., Khambatta Securities Limited has handled 11 public issues (2 main board IPOs & 9 SME IPOs) in the past three years preceding the date of Prospectus, out of which 3 SME IPOs closed below offer price on listing date.

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares Allotted per applicant	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
8	1,470	62	0.16	91,140	0.23	980	1:62	980
9	1,960	70	0.18	1,37,200	0.34	980	1:70	980
10	2,100	49	0.13	1,02,900	0.26	980	1:49	980
11	2,310	332	0.85	7,66,920	1.93	980	5:332	4,900
12	2,380	50	0.13	1,19,000	0.30	980	1:50	980
13	4,690	71	0.18	3,32,990	0.84	980	1:71	980
14	1,540	15	0.04	23,100	0.06	980	0:0	0
15	1,610	17	0.04	27,370	0.07	980	0:0	0
16	1,680	17	0.04	28,560	0.07	980	0:0	0
17	1,750	30	0.08	52,500	0.13	980	0:0	0
18	1,820	11	0.03	20,020	0.05	980	0:0	0
19	1,890	27	0.07	51,030	0.13	980	0:0	0
20	2,030	7	0.02	14,210	0.04	980	0:0	0
21	2,170	7	0.02	15,190	0.04	980	0:0	0
22	2,240	16	0.04	35,840	0.09	980	0:0	0
23	2,450	22	0.06	53,900	0.14	980	0:0	0
24	2,520	1	0.00	2,520	0.01	980	0:0	0
25	2,590	1	0.00	2,590	0.01	980	0:0	0
26	2,660	4	0.01	10,640	0.03	980	0:0	0
27	2,730	1	0.00	2,730	0.01	980	0:0	0
28	2,800	13	0.03	36,400	0.09	980	0:0	0
29	2,870	6	0.02	17,220	0.04	980	0:0	0
30	2,940	14	0.04	41,160	0.10	980	0:0	0
31	3,010	4	0.01	12,040	0.03	980	0:0	0
32	3,150	3	0.01	9,450	0.02	980	0:0	0
33	3,290	3	0.01	9,870	0.02	980	0:0	0
34	3,360	3	0.01	10,080	0.03	980	0:0	0
35	3,500	12	0.03	42,000	0.11	980	0:0	0
36	3,570	3	0.01	10,710	0.03	980	0:0	0
37	3,640	2	0.01	7,280	0.02	980	0:0	0
38	3,710	3	0.01	11,130	0.03	980	0:0	0
39	3,780	5	0.01	18,900	0.05	980	0:0	0
40	3,850	1	0.00	3,850	0.01	980	0:0	0
41	3,920	4	0.01	15,680	0.04	980	0:0	0
42	4,060	2	0.01	8,120	0.02	980	0:0	0
43	4,200	1	0.00	4,200	0.01	980	0:0	0
44	4,270	1	0.00	4,270	0.01	980	0:0	0
45	4,340	1	0.00	4,340	0.01	980	0:0	0
46	4,410	3	0.01	13,230	0.03	980	0:0	0
47	4,480	2	0.01	8,960	0.02	980	0:0	0
48	4,550	1	0.00	4,550	0.01	980	0:0	0
49	4,620	3	0.01	13,860	0.03	980	0:0	0
Please Note : 1 (One) lot of 980 shares have been allocated to all the Applicants from Serial No.14 to 49 = 2940 shares in ratio of 3:266							3:266	2,940
4 Additional share will be allotted to successful allottees from Sr no. 2 to 49 = 140 shares							1:1	140
1 Additional share will be allotted to successful allottees from Sr no. 2 to 49 = 30 shares in ratio of 30:35							30:35	30
	Total	39,030	100.00	3,97,79,250	100.00			5,94,050

C. Allotment to Non-Institutional Bidders (more than ₹1.00 million) (After Technical Rejections) (including ASBA Applications)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders (more than ₹ 1.00 million), who have bid at the Offer Price of ₹212 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 63.60 times. The total number of Equity Shares allotted in this category is 11,88,100 Equity Shares to 1,212 successful applicants. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under: (Sample)

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
1	4,760	13,808	94.98	6,57,26,080	86.98	980	1:12	11,27,980
2	4,830	199	1.37	9,61,170	1.27	980	17:199	16,660
3	4,900	170	1.17	8,33,000	1.10	980	7:85	13,720
4	4,970	31	0.21	1,54,070	0.20	980	3:31	2,940
5	5,040	36	0.25	1,81,440	0.24	980	1:12	2,940
6	5,110	22	0.15	1,12,420	0.15	980	1:11	1,960
7	5,180	21	0.14	1,08,780	0.14	980	2:21	1,960
8	5,250	27	0.19	1,41,750	0.19	980	2:27	1,960
9	5,320	8	0.06	42,560	0.06	980	1:8	980



पंजाबी नृत्य और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-4/7 के विद्यार्थी राज्यस्थानी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा 'डबल शो' राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुशांत लोक सेक्टर-43 के विद्यार्थी हरियाणवी नृत्य और ब्लू वेल्स स्कूल, सेक्टर-4 के विद्यार्थी नारी सशक्तिकरण पर आधारित विशेष प्रस्तुति देंगे। विद्यार्थियों द्वारा जैकबपुरा के स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोट क्लब्डियॉ शामिल होंगी। स्वतंत्रता सेनानी होंगे सम्मानित। समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर बलिदानियों के परिजनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह का समापन राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 की छात्राओं द्वारा राष्ट्रागन की प्रस्तुति के साथ होगा।

CATVISION LIMITED
(CIN: L92111DL1985PLC021374)
Regd. Office: H-17/202, 2nd Floor, Vikas Marg, Delhi-110092
Website: www.catvisionindia.com
E-mail: catvision@catvisionindia.com, Tel.: +91(120) 4229116
Toll Free No: 7669300112, 18001037032

**STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE
AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR
THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026**

The Board of Directors of the Company, at their Meeting held on 13th August 2026, approved the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026. The results, along with the Auditors' Report, have been posted on the Company's website at www.catvisionindia.com and can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Syed Athar Abbas
Managing Director
DIN: 00770259

Place: Noida
Date: August 13, 2026
Note:

The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Sr. No.	Category	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Equity Shares applied	% to Total	No. of Equity Shares allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares allotted
69	47,040	1	0.01	47,040	0.06	980	0:0	0
70	47,110	2	0.01	94,220	0.12	980	0:0	0
71	70,000	1	0.01	70,000	0.09	980	0:0	0
72	71,190	1	0.01	71,190	0.09	980	0:0	0
73	80,150	1	0.01	80,150	0.11	980	0:0	0
74	1,40,000	1	0.01	1,40,000	0.19	980	0:0	0
75	1,89,000	1	0.01	1,89,000	0.25	980	0:0	0
76	23,59,000	2	0.01	47,18,000	6.24	980	0:0	0
Please Note : 1 (One) lot of 980 shares have been allocated to all the Applicants from Serial No.18 to 76 = 4,900 shares in ratio of 5:102							5:102	4,900
1 Additional share will be allotted to successful allottees from Sr no. 1 to 76 = 340 shares in ratio of 340:1,212							340:1212	340
GRAND TOTAL		14,539	100.00	7,55,66,260	100.00			11,88,100

Allotment to QIBs, who have bid at the Offer Price of ₹ 212 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 42.13 times of Net QIB portion. As per the SEBI Regulations, Mutual Funds were allotted 5% of the Equity Shares of Net QIB portion available i.e. Nil Equity Shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available Equity Shares i.e. 23,76,690 Equity Shares (i.e., Includes spilled over of 1,18,835 Equity Shares from QIB MF category) on a proportionate basis. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 23,76,690 Equity Shares, which were allotted to 51 successful Applicants.

The Company, in consultation with the BRLMs, have allocated 35,63,810 Equity Shares to 4 Anchor Investors (through 4 Anchor Investor Application Forms) (including Nil domestic Mutual Funds through Nil schemes) at an Anchor Offer Price at ₹212 per Equity Share in accordance with SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB portion.

The Board of Directors of our Company at its meeting held on August 12, 2026 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation and/or notices have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been issued for unblocking of funds and transfer to the Public Offer Account on August 12, 2026 and the payments to non-syndicate brokers have been issued on August 13, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Offer at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees have been uploaded on August 13, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed the Listing application with BSE and NSE on August 13, 2026. The Company has received the listing and trading approval from BSE & NSE, and trading will commence on August 14, 2026.

1. On the second cover page and under the section titled "Definitions and Abbreviations", "General Information", "Terms of the Offer" and "Offer Procedure" on pages 6, 11, 110, 562, 598 and 599 respectively of the Red Herring Prospectus, the reference of Hindi National daily newspaper "Jansatta" shall be replaced with "Business Standard".

2. Under the Risk Factor No. 15 on page 49 of the Red Herring Prospectus, the variation amount for FY 2025-26 shall be modified as "₹ (35.87) million".

3. The sub-section titled "Key Justification for the projected Working Capital Requirements - Robust Order Book" on page 143 of the Red Herring Prospectus, shall be modified as follows:
"As on July 15, 2026, our outstanding order book is at ₹ 13,207.32 million, which will be completed within next 3 to 4 years. Apart from the outstanding work orders in hand of ₹ 13,207.32 million, the company has also been recently awarded L1 status by Delhi Jal Board under AMRUT 2.0 valuing ₹ 1,964.68 million."

4. The sub-section titled "Joint Ventures of our Company – Our History and Certain Corporate Matters" on page 333 of the Red Herring Prospectus, shall be modified as follows:
"Except as disclosed in this Red Herring Prospectus, our Company does not have any joint ventures."

5. The sub-section titled "Disposal of investor grievances by listed group companies and listed subsidiary – Other Regulatory and Statutory Disclosures" on page 561 of the Red Herring Prospectus, shall be modified as follows:
"As at the date of this Red Herring Prospectus, we do not have any listed group company or subsidiary, except as follows:
VVIP Infratech Limited is a listed company and is forming part of our group companies due to the related party transactions in the Financial Year ended on March 31, 2026, March 31, 2025 and March 31, 2024 but our Company and Promoters do not have any control or voting rights in this group company."

The information above modifies and updates the information (as applicable) in the RHP. The RHP accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP. Please note that this Corrigendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the RHP and the date hereof, and the relevant changes shall be reflected in the Prospectus filed with the RoC, SEBI and the Stock Exchanges. "For further details kindly refer RHP dated July 30, 2026 filed with RoC"

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Offer quoting full name of the First/ Sole applicant, Serial number of the Bid cum Application form number, Bidders DP ID, Client ID, PAN, date of submission of Bid cum Application Form, address of the Bidder, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 KHAMBATTA SECURITIES LIMITED 806, World Trade Tower, Tower B, Noida Sector-16, Uttar Pradesh-201301, India Tel.: +91 9953989693; 0120 4415469 E-mail: ipo@khambattasecurities.com Investor Grievance E-mail: mbcomplaints@khambattasecurities.com Contact Person: Chandan Mishra/ Shubhra Website: www.khambattasecurities.com SEBI Registration Number: INM000011914	 BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400093, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6263 8200 E-mail: ipo@bigshareonline.com Investor Grievance E-mail: investor@bigshareonline.com Contact Person: Babu Ropheal Website: www.bigshareonline.com SEBI Registration Number: INR000001385	Shefali Kesarwani S 553/54, Ground Floor, School Block, Shakarpur, New Delhi-110092, India. Tel.: +91 7835008595 E-mail: compliance@technocraftventures.com Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, the BRLM or the Registrar to the Offer in case of any pre-offer or post-offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode. For all offer related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLM.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

TECHNOCRAFT VENTURES LIMITED has filed a Prospectus dated August 12, 2026 with Registrar of Companies, Delhi, Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), BSE Limited (“BSE”) and the National Stock Exchange of India (“NSE”, together with “BSE”, the “Stock Exchanges”). The Prospectus is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM at www.khambattasecurities.com, the website of the Company at www.technocraftventures.com and websites of BSE and NSE i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. Any potential investor should note that an investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, kindly refer “**Risk Factors**” beginning on page 33 of the Prospectus. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI and Stock Exchanges for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws of the United States, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold (i) to persons in the United States or to or for the account or benefit of, U.S. Persons, in each case to investors that are both “qualified institutional buyers” (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) and referred to in the Red Herring Prospectus as “U.S. QIBs”) and, for the avoidance of doubt, the term U.S. QIBs does not refer to a category of institutional investor defined under applicable Indian regulations and referred to in the Red Herring Prospectus as “QIBs”; and “qualified purchasers” (as defined in the U.S. Investment Company Act and referred to in the Red Herring Prospectus as “QPs”) in transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and in reliance on Section 3(c)(7) of the U.S. Investment Company Act; or (ii) outside the United States to investors that are not U.S. Persons in offshore transactions (as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur).

For **Technocraft Ventures Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Shefali Kesarwani
Secretary and Compliance Officer

लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास का जीवंत दस्तावेज है एक अनोखी दास्तान

उमेश कुमार सिंह

लखनऊ। वरिष्ठ लेखक लव भाग्व की पुस्तक एक अनोखी दास्तान केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि इतिहास, विरासत, संघर्ष, संस्कृति और आत्मअन्वेषण का ऐसा जीवंत दस्तावेज है, जिसमें एक व्यक्ति के जीवन के साथ-साथ बदलते भारतीय समाज और समय की भी तस्वीर दिखाई देती है। पुस्तक की शुरूआत लेखक के गौरवशाली पारिवारिक इतिहास से होती है। महान प्रकाशक मुंशी नवल किशोर की विरासत से जुड़े परिवार की कहानी भारतीय प्रकाशन जगत के स्वर्णिम इतिहास से पाठकों को परिचित कराती है। नवल किशोर प्रेस की स्थापना, भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण ग्रंथों के प्रकाशन तथा साहित्यिक और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के प्रयासों का उल्लेख पुस्तक को ऐतिहासिक महत्व प्रदान करता है। बचपन की फुसफुसाहटें अध्याय में लखनऊ की तहजीब, पारिवारिक वातावरण, विशाल हवेली, पुराने नौकरों, ऐतिहासिक प्रिंटिंग प्रेस, स्कूल जीवन, पारिवारिक संबंधों और बचपन की भावनात्मक स्मृतियों का अत्यंत आत्मीय चित्रण किया गया है। लेखक की सहज शैली पाठक को उनके बचपन के दौर में ले जाती है और पारिवारिक जीवन की खुशियों, तनावों, अनुशासन तथा संघर्षों से रूबरू कराती है। पुस्तक में लखनऊ स्वयं एक महत्वपूर्ण पात्र की तरह उपस्थित दिखाई देता है। नवाबी विरासत, गंगा-जमुनी संस्कृति, खानपान, साहित्य, स्थापत्य और सामाजिक जीवन के माध्यम से लेखक ने शहर की उस सांस्कृतिक पहचान को सामने रखा है, जिसने देशभर में लखनऊ को विशिष्ट स्थान दिलाया। विभिन्न इतिहासकारों और लेखकों के संदर्भ पुस्तक के ऐतिहासिक पक्ष को और मजबूत करते हैं। जवानी की गर्मी में लेखक के संघर्षशील और प्रयोगधर्मी व्यक्तित्व का विस्तार दिखाई देता है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ऋद्धक) में चयन तथा फिल्म, संगीत और कला जगत की अनेक प्रसिद्ध हस्तियों से जुड़े संस्मरण पुस्तक को विशेष रूप से रोचक बनाते हैं। यश चोपड़ा, रोमेश शर्मा, दुर्गा खोटे, शंकर-जयकिशन, मोहम्मद रफी, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, बेगम अख्तर, अनूप जलोटा, वैजयंतीमाला और पद्मा सुब्रह्मण्यम जैसी विभूतियों से संबंधित प्रसंग पाठकों को उस दौर की सांस्कृतिक दुनिया की झलक देते हैं। डायमंड पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक एक अनोखी दास्तान का दायरा साहित्य और फिल्म जगत से कहीं आगे तक जाता है। राजनीति, उद्योग, व्यापार, सामाजिक सेवा, चिकित्सा, विदेश यात्राओं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े अनुभव भी इसमें शामिल हैं। लोह अयस्क व्यापार, मध्य अफ्रीकी गणराज्य से जुड़े कूटनीतिक प्रयास, स्वास्थ्य क्षेत्र में लैप्रोस्कोपी कार्यक्रम तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रयोगों की सफलता और असफलताओं को लेखक ने आत्मस्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक की एक बड़ी विशेषता पाठकों भाषा और कला प्रति शैली है। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण और संवादात्मक भाषा पाठक को लगातार जोड़े रखती है। व्यक्तिगत संस्मरणों और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच लेखक ने संतुलन स्थापित किया है। उनकी आत्मस्वीकृति इस कृति को विशेष विश्वसनীয়ता प्रदान करती है, क्योंकि उन्होंने केवल उपलब्धियों को ही नहीं, बल्कि असफलताओं, आर्थिक चुनौतियों, पारिवारिक मतभेदों, अधूरे सपनों और भावनात्मक संघर्षों की भी खुलकर सामने रखा है। पुस्तक वर्तमान और भविष्य से भी संवाद करती है। शिक्षा, तकनीकी विकास, उद्यमिता, नई पीढ़ी और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लेखक के विचार इसे केवल अतीत की कहानी नहीं रहने देते, बल्कि समकालीन संदर्भों से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर घटनाओं और व्यक्तियों का विवरण लंबा हो जाता है तथा अनेक नाम और प्रसंग सामान्य पाठक के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कुछ अध्यायों का संपादन अधिक संक्षिप्त होता तो पुस्तक की गति और प्रभाव और बेहतर हो सकता था। फिर भी इसकी व्यापक सामग्री और ऐतिहासिक महत्व के सामने यह कमी गौण है। समीक्षक उमेश कुमार सिंह के अनुसार, एक अनोखी दास्तान एक व्यक्ति के जीवन की कथा से आगे बढ़कर भारतीय समाज, संस्कृति, प्रकाशन, राजनीति, फिल्म, व्यापार और बदलते समय का बहुआयामी दस्तावेज बन जाती है। इतिहास, संस्मरण, आत्मचिंतन और प्रेरणा का यह संगम पुस्तक को विशिष्ट बनाता है।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

सुरेश सिंह बैस शावरत 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम प्रभात था, जब सदियों की गुलामी की अंधेरी रात समाप्त हुई और स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ। यह स्वतंत्रता लाखों ज्ञात-अज्ञात क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और असंख्य बलिदानों की अमूल्य धरोहर है। आज, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तब यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी है। यह समय है यह देखने का कि हमने सात दशकों से अधिक की यात्रा में क्या पाया, कहां पहुँचे और किन चुनौतियों से अभी भी जूझ रहे हैं। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से कमजोर, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी और सामाजिक विषमताओं से घिरा हुआ देश था। सीमित संसाधनों और अनेक कठिनाइयों के बावजूद भारत ने लोकतंत्र को न केवल अपनाया, बल्कि उसे सफलतापूर्वक सशक्त भी बनाया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति और रश्मि क्रांति ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमान, मंगलयान और आदित्य मिशनों के माध्यम से विश्व में भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परचम लहराया है। डिजिटल क्रांति ने भारत को विश्व के सबसे बड़े डिजिटल भूतान और तकनीकी नवाचार वाले देशों में स्थापित किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रेल, मेट्रो, एक्सप्रेस-वे, बंदरगाह, हवाई अड्डों और संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। महिलाओं की शिक्षा, पंचायतों में भागीदारी, सेना और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भूमिका सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक संकेत है। खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। किन्तु उपलब्धियों के इस उज्ज्वल पक्ष के साथ अनेक चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं। आज भी बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता, भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, कृषि संकट, साइबर अपराध, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और सामाजिक वेमनस्य जैसी समस्याएँ राष्ट्रीय विकास की गति को प्रभावित करती हैं। तकनीकी प्रगति के बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल चुनावों में नहीं, बल्कि नागरिकों के चिंतन, कर्तव्यनिष्ठा और सवैधानिक मूल्यों के सम्मान में निहित होती है। यदि नागरिक ईमानदारी, अनुशासन, सामाजिक समरसता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें, तो भारत का विकास और अधिक तीव्र गति से संभव होगा। आज विश्व तेजी से कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और ज्ञान-आधारित विकास की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में भारत के युवाओं, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, किसानों, उद्यमियों और श्रमिकों पर विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।आत्मनिर्भरता, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के संतुलन से ही भारत 21वीं सदी का नेतृत्व कर सकता है। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्यों का भी आह्वान है। देश के प्रति प्रेम केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ईमानदारी से कार्य करना, कानून का पालन करना, प्रकृति की रक्षा करना, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना ही सच्ची देशभक्ति है। आइए, स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में हम उन अमर राहियों को श्रद्धापूर्वक नमन करें, जिन्होंने अपने पाणों का सौच्यो बलिदान देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया। साथ ही यह संकल्प लें कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे जो समृद्ध, शिक्षित, वैज्ञानिक, संवेदनशील, आत्मनिर्भर और विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बने।

पुरुषार्थ जगाएं, व्यसन त्यागें : सफलता और सुख का यही सच्चा मार्ग

इसके विपरीत जब मनुष्य पुरुषार्थ छोड़कर आलस्य, निराशा और व्यसनोँ का सहारा लेने लगता है, तब उसकी क्षमताएं धीरे-धीरे क्षीण होने लगती हैं। इसलिए जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ जगाना तथा दुर्यंसनों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसंग से इसकी प्रेरणा मिलती है। वहां अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। एक सत्याग्रही को जोहनसबर्ग की जेल में बंद कर दिया गया। जेल में सभी कैदियों से काम कराया जाता था। अधिकांश कैदी किसी तरह अपना काम पूरा करते, लेकिन एक कैदी निर्धारित समय से पहले ही अपना कार्य पूरा कर लेता और बचे हुए समय में ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता रहता। एक दिन जेल का निरीक्षण करने आए अंग्रेज गवर्नर ने उससे पूछा कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। उस कैदी ने कहा कि यहां पूरा काम नहीं मिलता। गवर्नर को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि जब दूसरे कैदी काम से बचने का प्रयास करते हैं तो वह अधिक काम क्यों करना चाहता है। कैदी ने उत्तर दिया कि वह इसलिए अधिक काम करता है ताकि उसकी मेहनत करने की क्षमता नष्ट न हो जाए। यह साधारण-सा कैदी आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का महानायक बना। वह थे महात्मा गांधी।



मनुष्य के जीवन की वास्तविक पहचान उसके पुरुषार्थ से होती है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि व्यक्ति के भीतर परिश्रम करने, संघर्ष करने और आगे बढ़ने का संकल्प है तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। इसके विपरीत जब मनुष्य पुरुषार्थ छोड़कर आलस्य, निराशा और व्यसनोँ का सहारा लेने लगता है, तब उसकी क्षमताएं धीरे-धीरे क्षीण होने लगती हैं। इसलिए जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ जगाना तथा दुर्यंसनों से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसंग से इसकी प्रेरणा मिलती है। वहां अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। एक सत्याग्रही को जोहनसबर्ग की जेल में बंद कर दिया गया। जेल में सभी कैदियों से काम कराया जाता था। अधिकांश कैदी किसी तरह अपना काम पूरा करते, लेकिन एक कैदी निर्धारित समय से पहले ही अपना कार्य पूरा कर लेता और बचे हुए समय में ज्ञानवर्धक

स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक और विरघटियालयों से लेकर सड़कों तक छात्र आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्र जब अपनी पढ़ाई, रोजगार, परीथा, फीस, छात्रवृत्ति, आरक्षण, संस्थागत सुविधाओं अथवा भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लोकतंत्र में उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब छात्र आंदोलन का चेहरा छात्र होते हैं, मगर उसके पीछे की पटकथा किसी और की होती है। सवाल तब और गंभीर हो जाता है, जब एक ही प्रकार के आंदोलन को अलग-अलग राजनीतिक दल और विचारधाराएं सत्ता में अपनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग नजरिए से देखने लगती हैं। आज हमारे सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या छात्र आंदोलन वास्तव में छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है या राजनीतिक दलों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का माध्यम ? पिछले एक महीने में देश ने दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची में चल रहे छात्र आंदोलन जैसे दो अलग-अलग घटनाक्रमों को देखा है। दोनों जगह युवा सड़क पर हैं। कहीं भूख हड़ताल है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, कहीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है।



भारत में छात्र आंदोलन कोई नई घटना नहीं है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में छात्र शक्ति ने कई बार सत्ता को चुनौती दी है, व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई है और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन की दिशा तय की है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक और विश्वविद्यालयों से लेकर सड़कों तक छात्र आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्र जब अपनी पढ़ाई, रोजगार, परीथा, फीस, छात्रवृत्ति, आरक्षण, संस्थागत सुविधाओं अथवा भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लोकतंत्र में उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब छात्र आंदोलन का चेहरा छात्र होते हैं, मगर उसके पीछे की पटकथा किसी और की होती है। सवाल तब और गंभीर हो जाता है, जब एक ही प्रकार के आंदोलन को अलग-अलग

सुनील कुमार महला	
	
15 अगस्त 2026 का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव, उत्साह और देशभक्ति का अवसर है। इस वर्ष हम भारत की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ पूरी होने के बाद 80वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पाठक जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।स्वतंत्रता दिवस का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा होता है। तिरंगा केवल तीन रंगों से बना एक ध्वज नहीं, बल्कि यह भारत की स्वतंत्रता, संग्रभुता, एकता, विविधता और असंख्य स्वतंत्रता समानियों के बलिदान का प्रतीक है। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा	

विचार मंथन

हुए सबके कल्याण और अभ्युदय की भावना प्रस्तुत की। भगवान महावीर ने भी समाज में समानता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती देते हुए धर्म का द्वार सभी के लिए खोलने की प्रेरणा दी। उनका संदेश स्पष्ट था कि मनुष्य अपने व्यक्ति के लिए सफलता की राह खुलती जाती है। जीवन में अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन उनका लाभ वही उठा पाता है जो समय पर प्रयास करता है। एक छोटी-सी घटना इस बात को बहुत सरलता से समझाती है। सड़क पर बैलगाड़ी जा रही थी और कुछ बच्चे उसके साथ चल रहे थे। गाड़ी देखकर कुछ बच्चे दौड़कर उसमें चढ़ गये, जबकि कुछ पीछे रह गए। गाड़ीवान से पूछा गया कि कुछ बच्चे पीछे क्यों रह गए। उसने सहज उत्तर दिया कि जिनमें हिम्मत और पुरुषार्थ था, वे गाड़ी में चढ़ गए। यह प्रसंग जीवन का भी सत्य है। अवसर

दिल्ली से रांची तक उठते सवाल - आंदोलन मुद्दे से तय होता है या सत्ता किसके हाथ में?

स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक और विरघटियालयों से लेकर सड़कों तक छात्र आंदोलनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छात्र जब अपनी पढ़ाई, रोजगार, परीथा, फीस, छात्रवृत्ति, आरक्षण, संस्थागत सुविधाओं अथवा भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो लोकतंत्र में उनकी आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। लेकिन सवाल तब पैदा होता है, जब छात्र आंदोलन का चेहरा छात्र होते हैं, मगर उसके पीछे की पटकथा किसी और की होती है। सवाल तब और गंभीर हो जाता है, जब एक ही प्रकार के आंदोलन को अलग-अलग राजनीतिक दल और विचारधाराएं सत्ता में अपनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग नजरिए से देखने लगती हैं। आज हमारे सामने यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या छात्र आंदोलन वास्तव में छात्रों के अधिकारों की लड़ाई है या राजनीतिक दलों के लिए अपनी जमीन मजबूत करने का माध्यम ? पिछले एक महीने में देश ने दिल्ली के जंतर-मंतर और रांची में चल रहे छात्र आंदोलन जैसे दो अलग-अलग घटनाक्रमों को देखा है। दोनों जगह युवा सड़क पर हैं। कहीं भूख हड़ताल है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, कहीं मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है।

हाथ में है ? दिल्ली में सत्ता के खिलाफ उठने वाली छात्र आवाज के साथ जो लोग खड़े दिखाई देते हैं, वे रांची में उसी तरह की छात्र बेचैनी से दूरी क्यों बना लेते हैं ? यदि छात्रों की समस्या वास्तव में समस्या है, तो फिर सरकार बदलते ही उसके प्रति संवेदनशीलता क्यों बदल जाती है ? यहीं से छात्र आंदोलन को प्रभावित करती रही है। छात्रों के सामने कई वास्तविक समस्याएं होती हैं। परीथा व्यवस्था में गड़बड़ी, परिणाम में देरी, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता, बेरोजगारी, फीस में वृद्धि, छात्रवृत्ति का भुगतान न होना, हॉस्टल की समस्या, शिक्षकों की कमी, प्रतियोगी परीथाओं की पारदर्शिता और सरकारी नौकरियों में अवसर जैसे

ध्वजारोहण या ध्वज फहराना : 80वें स्वतंत्रता दिवस पर जानिए दोनों में फर्क

ऊन, रेशम और खादी के बॉटिंग के उपयोग की अनुमति दी गई। इस प्रकार अब केवल खादी से बने ध्वज तक यह व्यवस्था सीमित नहीं रही।इसके बाद 20 जुलाई 2022 को भारतीय ध्वज संहिता में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इसके तहत किसी नागरिक के घर पर राष्ट्रीय ध्वज को दिन और रात दोनों समय फहराने की अनुमति दी गई। इसलिए सूर्यास्त के बाद घर पर तिरंगा उतारना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, रात में ध्वज फहराते समय उसकी गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय ध्वज सफा-सुथरा, सही स्थिति में और सम्मानजनक एवं प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित होना चाहिए। केसरिया पट्टी हमेशा ऊपर की



सामने आने पर जो व्यक्ति प्रयास करता है, वही आगे बढ़ता है। आज पुरुषार्थ की सबसे बड़ी आवश्यकता व्यसनोँ से बचने के लिए है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के आकर्षण और बुरी आदतें मौजूद हैं। नशा और अन्य दुर्य्यसन व्यक्ति की सोच, समय, धन और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। व्यसन केवल व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि परिवार और समाज को भी कमजोर करते हैं। एक व्यक्ति की बुरी आदत धीरे-धीरे पूरे परिवार को आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसलिए व्यसन से दूर रहना भी अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ है। समाज में व्यसन-मुक्ति के लिए अनेक अभियान चलाए जाते हैं। सरकार और सामाजिक संस्थाएं लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करती हैं। सभाएं होती हैं, जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन केवल अभियान चलाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। इसके लिए

परिवार, समाज और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस व्यक्ति में स्वयं अनुशासन नहीं है, वह दूसरों को अनुशासन का संदेश प्रभावी ढंग से नहीं दे सकता। इसलिए व्यसन-मुक्त समाज की शुरूआत स्वयं से करनी होगी। व्यसन व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को कमजोर कर देते हैं। एक प्रसिद्ध प्रसंग में एक व्यक्ति को यह अवसर दिया गया कि वह चार विकल्पों में से किसी एक को चुने। उसने आसान समझकर शराब का रास्ता चुना, लेकिन नशे के प्रभाव में उसके विवेक पर नियंत्रण नहीं रहा और एक गलत निर्णय दूसरे गलत निर्णय को जन्म देता चला गया। इस प्रसंग का संदेश यही है कि व्यसन अक्सर अकेला नहीं आता। एक बुरी आदत दूसरी बुरी आदत का रास्ता खोल सकती है और व्यक्ति धीरे-धीरे अपने विवेक तथा आत्मनियंत्रण को खो सकता है। इसीलिए व्यसन को केवल एक व्यक्तिगत आदत मानना प्याप्त नहीं है। यह परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक वातावरण से जुड़ी समस्या है। जिस



उठाए, आंदोलनकारी छात्रों के साथ खड़ा हो, उनकी मांगों को संसद या विधानसभा में उठाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ हो, यह मान लेना छात्रों के संघर्ष को कमतर आंकना होगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि राजनीति छात्र आंदोलनों को प्रभावित करती रही है। छात्र संगठन लंबे समय से राजनीतिक विचारधाराओं की प्रयोगशाला रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बने वाली राजनीतिक चेतना आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। यही कारण है कि छात्र आंदोलन आंदोलनों को प्रभावित करती रही है। इसी तरह यदि सत्ता पक्ष अपने शासन वाले राज्य में छात्रों की मांग को गंभीरता से लेने के बजाय उसे विपक्ष की साजिश बताता है, जबकि दूसरे रूपर स्थित ध्वज को खोलकर अथवा फैलाकर हवा में लहराना। इस दृष्टि से दोनों क्रियाओं की प्रकृति अलग है। भारत के राष्ट्रीय पर्वों में इस अंतर को समझने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके विपरीत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करते हैं।इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि 15 अगस्त को ध्वज

फहराया जाता है और 26 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाता है। इसके पीछे दोनों राष्ट्रीय पर्वों की ऐतिहासिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय ब्रिटिश शासन के प्रतीकात्मक रूप से हटने और स्वतंत्र भारत के उदय का संदेश देते हुए तिरंगे को ऊपर फहराया गया। दूसरी ओर, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना।इसलिए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा स्थापित हुई। हालांकि सामान्य बोलचाल में ध्वजारोहण और ह्यध्वज फहरानाहू कई बार समान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और सरकारी अथवा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी दोनों शब्द सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पर्वों की विशिष्ट संवैधानिक एवं ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त के लिए

संक्षिप्त खबरें

पंखा अपनी ओर खींचते ही लगा करंट , परिवार के इकलौते सहारे की मौत
 मीरजापुर। जमालपुर थाना क्षेत्र के पिंडिसिर गांव में गुरुवार दोपहर 45 वर्षीय मुन्ना मुसहर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। फरार्ट पंखे का स्विच ऑन कर उसे अपनी ओर खींचते समय पंखे में उतर रहे करंट ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि मुन्ना दोपहर करीब दो बजे घर में फरार्ट पंखा चला रहे थे। स्विच ऑन करने के बाद वह पंखे को हाथ से अपनी ओर खींच रहे थे। इसी दौरान पंखे में उतर रहे करंट की चपेट में आकर वह उससे चिपक गए। परिजन कुछ समझा पते, इससे पहले ही मौके पर उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग और परिजन मौके पर जुट गए। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुन्ना परिवार का मुख्य सहारा थे और ईंट-भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी लक्ष्मीना और शीला तथा पुत्र पेजल और किशन का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन की चैख-पुकार से गांव का माहौल गमगीन हो गया। जमालपुर प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि करंट की चपेट में आने से अघेड़ की मौत हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

अब गांव-गांव होगी पानी की जांच, पंचायत सहायकों को मिली वाटर टेस्टिंग किट

मीरजापुर। गांवों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में जल जीवन मिशन ने कदम बढ़ाया है। गुरुवार को जमालपुर ब्लॉक सभागार में जल जीवन मिशन विभाग की ओर से पंचायत सहायकों को पानी की गुणवत्ता जांचने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 50 पंचायत सहायकों को वाटर टेस्टिंग किट वितरित की गई। प्रशिक्षक विकास मौर्य ने पंचायत सहायकों को किट के माध्यम से पानी की जांच करने की पूरी प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि समय-समय पर गांवों में पेयजल की जांच की जाएगी। वाटर टेस्टिंग किट की मदद से पानी में मौजूद विभिन्न रासायनिक पदार्थों और बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकेगा। पानी की जांच के लिए आवश्यक टैबलेट भी उपलब्ध कराई गई। प्रशिक्षक ने कहा कि दूषित पानी के सेवन से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नियमित जांच से पानी की गुणवत्ता का पता समय रहते लगाया जा सकेगा और लोगों को पीने योग्य शुद्ध पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के बाद पंचायत सहायकों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने-अपने गांवों में समय-समय पर पानी के छोटों की जांच करें और पानी की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी संबंधित विभाग तक पहुंचाएं। इस दौरान शैलेंद्र सिंह, सुजीत विश्वकर्मा, भानू यादव, पूजा कुमारी, रवि दुबे, सख्ता कुमारी, राजेश कुमार, सिमोन, आरिन यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सेमिनार आयोजित

युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए जागरूकता जरूरी: डॉ. लुबना हामिद

प्रातः किरण संवाददाता

अमरोहा। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नायाब अब्बासी डिग्री कॉलेज में नशे के खिलाफ जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्या डॉ. लुबना हामिद ने की। वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. एम. अथर कानून ने कहा कि वर्तमान समय में अभिभावकों को अपने बच्चों पर

बाढ़ प्रभावित 85 परिवारों को राहत किट वितरित पानी उतारने के बाद होगा कृषि क्षति का आकलन

प्रातः किरण अवनीश त्यागी

बिजनौर, 13 अगस्त। तहसील चांदपुर क्षेत्र में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को ग्राम रायपुर खादर में 85 प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की गई। पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत किट उपलब्ध कराई गई। उप जिलाधिकारी चांदपुर प्रशांत वर्मा ने बताया कि 14 अगस्त को ग्राम दतियाना के 49, जमालुद्दीनपुर के 35 और मीरापुर सीकरी के 140 प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित की जाएगी। शेष राशन किट प्राप्त होने के बाद अन्य प्रभावित परिवारों को भी राहत राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसील चांदपुर



क्षेत्र में 29 जुलाई से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। इससे मीरापुर सीकरी, सलेमपुर, दतियाना, सिंहाली, मुजफ्फरपुर खादर, जमालुद्दीनपुर, धीवरपुर, रायपुर खादर, जलालपुर खादर, कुम्हरिया, शुजातपुर खादर और खानपुर खादर सहित कई गांवों के खेत जलमग्न हुए हैं। 8 अगस्त के

बाद जलस्तर बढ़ने से कुछ गांवों की आबादी में भी पानी भर गया, जिससे कई परिवार प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों के लिए तहसील स्तर पर दो मानव चालित नाव और एक मोटरबोट उपलब्ध कराई गई हैं। दो नावें एक अगस्त तथा मोटरबोट आठ अगस्त को तहसील चांदपुर को उपलब्ध कराई गई थीं। इनका

दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी

इस सामग्री पर समाचार पत्र के लिए समाचार लिखिए

प्रातः किरण संवाददाता

बिजनौर। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, कर्मचारियों, खिलाड़ियों सहित अन्य पात्र लोगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिसंबर 2026 को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कुल 12 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें दक्ष दिव्यांग कर्मचारी अथवा स्वनिर्योजित दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्यात,



सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी, दिव्यांगजन के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एवं संस्था, प्रेरणास्रोत, जीवन में सुधार देने वाले, सर्वश्रेष्ठ नवीन अनुसंधान अथवा उत्पाद विकास, बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ सुशुनशील दिव्यांग व्यक्ति एवं बालक-बालिका, सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस, दिव्यांगजन के लिए सर्वोत्तम अनुकूल वेबसाइट, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी तथा दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए

नए श्रम कानूनों की रेल कर्मचारियों को दी गई

करीब 100 कर्मचारियों ने लिया हिस्सा, श्रम कानूनों के प्रावधानों, अधिकारों और कार्यस्थल सुस्था पर हुई विस्तृत चर्चा

प्रातः किरण संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल मुख्यालय स्थित सभागार में बुधवार को भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए श्रम कानूनों को लेकर विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती विनीता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अभिषेक ठाकुर के संयोजन में आयोजित सेमिनार में करीब 100 रेल कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। सेमिनार में अपर मंडल रेल प्रबंधक (ओपी)



श्री पारितोष गौतम सहित विभिन्न शाखाओं के प्रवर अधीनस्थ एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे। मुख्य वक्ता श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), बरेली श्री सरफराज किबरिया ने नए श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों, कर्मचारी कल्याण, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों

तथा कानूनों में किए गए प्रमुख बदलावों की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने नए श्रम कानूनों से जुड़े विभिन्न सवाल एवं जिज्ञासाएं मुख्य वक्ता के समक्ष रखीं। उन्होंने संबंधित प्रश्नों का समाधान करते हुए कानूनों के प्रावधानों को सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समझाया।सेमिनार का उद्देश्य रेल कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों को नए श्रम कानूनों के प्रति जागरूक करने के साथ उनके अधिकारों, दायित्वों और विधिक प्रावधानों की जानकारी देना रहा। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन कर्मचारियों को कानूनों में हुए बदलावों को समझने तथा कार्यस्थल पर उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

उपयोग प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जा रहा है। एस्डीएम के अनुसार बाढ़ प्रभावित परिवारों का राजस्व टीम द्वारा सर्वे कर सूची तैयार की गई है। राहत सामग्री के लिए जिला स्तर से 500 राशन किट की मांग की गई थी, जिसके सापेक्ष 320 किट प्राप्त हो चुकी हैं।

पानी उतरने के बाद होगा फसलों के नुकसान का सर्वे

वर्तमान में खेतों में पानी भरा होने के कारण कृषि क्षति का सही आकलन संभव नहीं है। जलस्तर कम होने और पानी उतरने के बाद राजस्व तथा कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा फसलों के नुकसान का सर्वे और आकलन कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार पात्र प्रभावित किसानों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

विदेश मेजने के नाम पर 19 लाख रुपये की ठगी का आरोपी गिरफ्तार

प्रातः किरण अवनीश त्यागी

बिजनौर। विदेश भेजने के नाम पर 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में चांदपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता के पुत्र को विदेश भेजने के नाम पर रकम ली थी। रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी

प्रातः किरण अवनीश त्यागी

बिजनौर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव के चलते बिजनौर तहसील क्षेत्र के ग्राम कुन्दनपुर के सामने कटान का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नदी अब गांव से महज 80 से 85 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है। तेजी से हो रहे कटान को देखते हुए ग्रामीणों में चिंता और भय का माहौल है। सभावित खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग की टीम ने मौके पर डेरा डाल दिया है और कटावरोधी सुरक्षात्मक कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिए हैं। ग्राम प्रधान के अनुसार यदि समय रहते कटान रोकने के प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए तो गांव की आबादी के साथ-साथ सैकड़ों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि भी गंगा की धारा में समाहित हो सकती है। ग्रामीणों ने नदी के कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग की है। मामले को गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी बिजनौर ने अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर के अधिशासी अभियंता



को तत्काल कटावरोधी सुरक्षात्मक कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ कनिष्ठ अभियंता नवीन शर्मा, चन्द्रकुश चौहान, महावीर सिंह, नरेश कुमार सहित अन्य कर्मचारी और राजस्व कर्मी निगरानी में जुटे हैं। अधिकारियों की ओर से कटान प्रभावित गांवों में लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा



है। जलप्रवाह तेज होने से नदी की धारा कटान कर रही है, जिसके चलते कुन्दनपुर क्षेत्र में खतरा बढ़ा है। राजस्व विभाग भी अलर्ट उप जिलाधिकारी सदर के निर्देश पर राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक और लेखापालों को भी मौके पर निगरानी के लिए निर्देशित किया गया है। सिंचाई और राजस्व विभाग की टीमों आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल प्रशासन के अनुसार स्थिति निर्वन्त्र में है। अधिशासी अभियंता अरूण सचदेवा ने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को कटावरोधी कार्य युद्धस्तर पर कराने तथा संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

बे लगाम भ्रष्टाचार पर आमजन के विचार

प्रातः किरण सुशील शर्मा

लोनी। राष्ट्रहित की मानसिकता वाले कुछ लोग रिश्ताखोरी पर लगाम लगाने के पक्षधर है, मगर उनकी गिनती शून्य के समान हैं। इस मामले में सरकार की बात करें तो, उसके द्वारा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के समय-समय पर दावे किए जाते रहे है, जबकि इसकी जमीनी हकीकत की बात करें तो सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. जो आम जनता के लिए आर्थिक नुकसान, जरूरी सेवाओं में देरी, मानसिक परेशानी और व्यवस्था से विश्वास उठने का कारण बनता जा रहा है। इससे गरीबों और जरूरतमंदों का सबसे अधिक शोषण होता है, क्योंकि उन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए भी रिश्तत या चक्कर काटने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण सख्त कानून का अभाव कहा जााएगा। भ्रष्टाचार के इसी मुद्दे को लेकर जब इस प्रतिनिधि ने कुछ संप्रभंत नागरिकों के मन की बात जानी तो उनका कथन कुछ इस प्रकार रहा:- -शिशु भारती पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक निमल शर्मा का कहना है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सख्त कानून व्यवस्था अपनाये तो रिश्तातखोरी पर नकेल लगाई जा सकती है। कानून कठोर होने से सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में भय उत्पन्न होगा और वह रिश्तात लेने के ऐसे कृत्य को बुरा रहेगा। -समाजसेवी अरती मिश्रा के अनुसार देने वाले के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई



जाना जरूरी है। -शकरपुर निवासी जेपी शर्मा ने कहा कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग का क्यों ना हो, यदि रिश्तात लेते पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमारे देश में कहीं ना कहीं आए दिन सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कड़ी कानून व्यवस्था के अभाव में वह बच जाते हैं. इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। दरअसल आमतौर पर रिश्तात लेने वाले कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ समय बाद उसकी पुनर्नियुक्ति हो जाती है। नतीजन भ्रष्टाचारी सोच के ऐसे कर्मचारियों में कोई डर-भय नहीं हैं। यदि रिश्तात लेने पर सीधे बर्खास्ती का कानून बन जाए तो उनकी भ्रष्टाचारी मानसिकता पर अंकुश लगेगा, क्योंकि उनमें नौकरी चले जाने का भय रहेगा। -समाजसेवी अरती मिश्रा के अनुसार आज के समय हर नागरिक किसी भी क्षेत्र में यही

तिरंगामय हुआ अमरोहा, देशभक्ति के नारों से गुंजा शहर

गव्य तिरंगा रैली में उमड़ा जनझेलाब, शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी श्रद्धांजलि

प्रातः किरण संवाददाता

अमरोहा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को अमरोहा में भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। होल-नगाड़ों, बेंड-बाजे और देशभक्ति गीतों के बीच निकली रैली में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया। तिरंगा रैली ज्योतिबापुले चौक से शुरू होकर शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती कान्ता कर्मा, पूर्व मंत्री मदन चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी, जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंडर, धनौरा विधायक राजीव तरारा, पूर्व सांसद देवेन्द्र



नागपाल, नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार मिश्र, जिला सूचना अधिकारी मो. दुनिश्वर सहित अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। रैली के दौरान हार्ददे मातरम्ह और हम्भारत माता की जयम्ह के नारों से वातावरण गुंज उठा। विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशप्रेम का संदेश दिया। लोगों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों

की प्राप्त की। मुख्य अतिथि कान्ता कर्दम ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आजादी हमें वीरों के बलिदान से मिली है। भाजपा जिलाध्यक्ष उदयगिरि गोस्वामी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और गौरव का भावना को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है विधायक राजीव तरारा ने नागरिकों से राष्ट्रध्वज सहिता का पालन करते हुए घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। पूर्व सांसद देवेन्द्र नागपाल ने कहा कि अभियान के माध्यम से सभी वर्गों के लोग राष्ट्रभक्ति के इस पर्व में सहभागीता कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने जिलेवासियों से अभियान में बहु-चटकर भाग लेने तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

गंगा एक्सप्रेसवे: जमीनों के सर्किल रेट 48% तक बढ़ेंगे

प्रातः किरण संवाददाता

अमरोहा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को गति देने के लिए अमरोहा जिला प्रशासन ने जिले में जमीनों के नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए हैं। एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले राजस्व ग्रामों में प्रचलित दरों की असमानता दूर करते हुए सर्किल रेट में अधिकतम 48 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रशासन का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आ रही अड़चनें कम होंगी और किसानों को उनकी भूमि का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ द्वारा जारी प्रस्तावित सर्किल रेट सूची में गंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों की दरों को आसपास के गांवों के अनुरूप करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा तहसील हसनपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से लगी कृषि भूमि के लिए भी नई दरें प्रस्तावित की गई हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ेंगी जमीनों की दरें

अमरोहा। प्रशासन की प्रस्तावित सूची के अनुसार सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल रेट में 10 फीसदी, जबकि आवासीय एवं कृषि भूमि वाले विकासशील क्षेत्रों में 15 फीसदी की वृद्धि प्रस्तावित है। वहीं नगरीय, लघुनगर नगरीय और अर्धनगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि भूमि की दरों में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर स्थित गांवों में कृषि



और अक्रषिक भूमि की दरों में स्थान के अनुसार 5 से 20 फीसदी तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिन राजस्व ग्रामों में जमीनी की दरों में अधिक असमानता है, वहां अधिकतम 30 फीसदी तक की वृद्धि कर दरों में समतुल्यता लाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही नगरीय, अर्धनगरीय और विनियमित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं जनपदीय मार्गों से लगी कृषि भूमि को बाजार मूल्य के करीब लाने के लिए बेल्टिंग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

भूमि अधिग्रहण में आगी तेजी

अमरोहा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की लेकर आने वाली दिक्कतों को दूर करने में नई प्रस्तावित दरें

चोरी के माल के साथ चार शातिर गिरफ्तार, सैट्रो कार भी बरामद

रजबपुर पुलिस ने फार्म हाउस चोरी का किया खुलासा, एलईडी, फ़िट्टर, टैबलेट और बाइक बरामद

प्रातः किरण संवाददाता

अमरोहा। रजबपुर थाना पुलिस ने मिलक मेहमदी स्थित फार्म हाउस से हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया 32 इंच का एलईडी टीवी, फ़िट्टर, सैमसंग टैबलेट, स्टेप्लाइज़र और होंडा सीडी 110 मोटरसाइकिल बरामद की है। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त सफेद रंग की सैट्रो कार संख्या वड20उ36084 को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम मिलक मेहमदी निवासी सतीश कुमार ने फार्म हाउस डिज़न प्लांट्स से 2 अगस्त की रात करीब दो बजे सामान चोरी होने की शिकायत की थी। मामले में 12 अगस्त को थाना रजबपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना



के खुलासे के लिए पुलिस टीम का संदिग्धों की तलाश और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही थी। इसी दौरान 13 अगस्त को उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मुखबिंर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल आरोपी चोरी के सामान को बेचने के लिए गुलड़िया रोड स्थित खालकपुर तिराहे के पास सैट्रो कार में खड़े हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कार के डैशबोर्ड से सैमसंग का टैबलेट, पिछली सीट से 32 इंच की हायर कंपनी की एलईडी तथा डिग्गी से सुल्तान कंपनी का स्टेप्लाइज़र और



मोदी सरकार ने संसद में हंगामे के बीच अडानी की दलाली वाला बिल पास कर दिया: संजय सिंह

● अब मोदी जी बिना किसी रोक-टोक के देश भर की खदानें अपने दोस्त अडानी को दे देंगे: संजय सिंह

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन बिल, 2026 का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में हंगामे के बीच अडानी की दलाली वाला बिल पास कर दिया। राज्यों का अधिकार छीन कर देश भर के सारे खनिजों पर केंद्र सरकार का कब्जा होगा। इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया गया और अब राज्य सरकार

संक्षिप्त खबरें इस चुनाव 18 सितंबर को परिणाम अगले दिन

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। इस चुनाव के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 19 सितंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीख सामने आने के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही नामांकन, प्रचार, मतदान और मतगणना से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। चुनाव की घोषणा के बाद छात्र संगठनों के पास विद्यार्थियों से संपर्क करने और प्रचार अभियान चलाने के लिए करीब 35 दिन का समय है। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर में गतिविधियां तेज होने की संभावना है। लनए सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों पर भी छात्र संगठनों की विशेष नजर है। एबीवीपी और एनएसयूआई सहित विभिन्न संगठन नए विद्यार्थियों से संपर्क कर अपनी गतिविधियों और छात्र हित से जुड़े कार्यों की जानकारी दे रहे हैं। चुनाव के दौरान विश्वविद्यालयों की आचार संहिता लागू रहेगी। पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री, वाहनों के इस्तेमाल और सभाओं सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधिअतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के साथ परिसर में शैक्षणिक गतिविधियां और यातायात व्यवस्था सामान्य बनाए रखने की चुनौती भी रहेगी।

मिलावटखोरी से आजादी की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली टैक्सि एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर खाद्य, दवाओं और ईंधन में मिलावट पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। संजय सम्राट ने कहा कि मिलावटखोरी सिर्फ आर्थिक घोरखा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य पर गंभीर संकट है। उन्होंने मिलावट पर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। एसोसिएशन ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलावे की नीति की स्वतंत्र वैज्ञानिक समीक्षा की मांग की है। इसी तरह सीएनजी में बायोगैस/सीबीजी मिलावे की नीति में भी गुणवत्ता, सुरक्षा और वाहन क्षमता की नियमित जांच की मांग की गई है।

डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार, युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित नमो विकसित भारत संवाद संदेशभक्ति और जिम्मेदार नागरिकता पर गहन चर्चा हुई। डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सेंटर फॉर नमो स्टडीज की ओर से संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी अंशु वर्मा ने कहा कि संविधान नागरिकों के प्रति गणतंत्र के दायित्व बताता है, जबकि धर्म समाज, राष्ट्र व आने वाली पीढ़ियों के प्रति हार्दिक जिम्मेदारियां याद दिलाता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे सोचें कि देश को क्या दे सकते हैं, न कि केवल क्या पा सकते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के डॉ. विनोद के वर्मा ने कहा कि संवैधानिक मूल्य व्यवहार में दिखने चाहिए। कार्यक्रम में डॉ. दिनेश दुबे, डॉ. मो. शम्स इकबाल, फिफोजे खान गाजी, डॉ. अमना मिर्जा समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे।



को कोई राजस्व नहीं मिलेगा। अब मोदी जी बिना किसी रोक-टोक

के देश भर की खदानें अपने दोस्त अडानी को दे देंगे। यह बिल राज्य

दिल्ली में जाम से राहत के लिए 1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़क और परिवहन परियोजनाओं पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में, यह जानकारी दी। गडकरी के अनुसार, करीब 1.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, जबकि 34,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और इन पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। इन योजनाओं में प्लाईओवर,



राष्ट्रीय राजमार्ग, सुरंग, भूमिगत मार्ग, अंडरपास और पैदल पुल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पूरी हो चुकी प्रमुख परियोजनाओं में दिल्ली-मेरठ द्रुतमार्ग, ईस्टर्न पेरिफेरल द्रुतमार्ग, डीएनडी से फरीदाबाद-सोहना होते हुए वडोदरा-मुंबई द्रुतमार्ग, द्वारका द्रुतमार्ग और दिल्ली-देहरादून द्रुतमार्ग शामिल हैं। वहीं, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क मार्ग तथा डीएनडी-महारानी बाग-जैतपुर जंक्शन और दिल्ली-मेरठ द्रुतमार्ग से 4 लेन संपर्क मार्ग

हर्ष मल्होत्रा ने अहिल्याबाई होल्कर की पुण्य तिथि पर दी उन्हें श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की पुण्य तिथि पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष संतोष पाल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अनुकरणीय सुशासन, जन कल्याण के प्रति समर्पण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण तथा देश भर में ऐतिहासिक मंदिरों के पुनर्निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने सभी को सम्बोधित करते हुए लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की पुण्य तिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा परिवार संकल्प लेता है कि हम अहिल्याबाई के सेवा, सुशासन और संस्कृति के मूल्यों पर चलकर विकसित भारत बनाएंगे। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अहिल्याबाई



होल्कर सिर्फ एक शासक नहीं थीं, वो जनसेवा की जीवंत मिसाल थीं। 18वीं सदी में उन्होंने नारी शक्ति का ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसे पूरा विश्व आज भी याद करता है। उन्होंने कहा कि राजधर्म ही उनका धर्म था, और सेवा ही उनकी पूजा थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मालवा

हाथ की मुट्ठी में छिपाकर लाया 100 ग्राम सोना, दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया



नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर सिंगापुर से आए एक यात्री के पास से करीब 100 ग्राम सोना बरामद किया। यात्री ने सोने को अपने हाथ की मुट्ठी में छिपा रखा था, ताकि सामान की स्कैनिंग के दौरान पकड़ में न आए। अधिकारियों के अनुसार, 12 अगस्त की रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंची इंडिगो की उड़ान 6 ई-1014 से उतरे दिल्ली निवासी यात्री को

किया। यात्री ने सोने को अपने हाथ की मुट्ठी में छिपा रखा था, ताकि सामान की स्कैनिंग के दौरान पकड़ में न आए। अधिकारियों के अनुसार, 12 अगस्त की रात सिंगापुर से दिल्ली पहुंची इंडिगो की उड़ान 6 ई-1014 से उतरे दिल्ली निवासी यात्री को



स्टेट स्थित दिल्ली सरकार का मौजूदा सचिवालय लगभग चार एकड़ जगह में बना हुआ है। यहां पर सभी मंत्रियों के कार्यालय के अलावा कुछ विभागों के भी दफ्तर हैं। दिल्ली सरकार भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सचिवालय

सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा और उनके आर्थिक शक्ति को खत्म करने का प्रयास है। सदन में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि यह बिल राज्यों के अधिकार छीनने वाला बिल है। केंद्र सरकार राज्य की बिजली, पानी और खनिजों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सरकार पूरे देश के खनिज पदार्थों पर कब्जा चाहती हैं? उन्होंने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच का फैसला 2024 में आया था। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों और खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार है। लेकिन केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी

भी नाम से कोई टैक्स या सेस नहीं लगाया जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि यह एक काला कानून है, जो राज्य सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने और उनकी आर्थिक शक्ति को खत्म करने का प्रयास है। यह बिल देश के चंद पूंजीपतियों को कोल ब्लॉक, माईन और खनिज देने के लिए लाया गया है। ओडिशा, तेलंगाना, बंगाल और तमिलनाडु जैसे तमाम राज्य, जहां माइनिंग होती है, वहां की माइनिंग पर केंद्र सरकार सीधे तौर पर कब्जा करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि यह बिल अडानी की दलाली के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार अडानी की दलाली करने के लिए यह बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार को राज्यों की माइनिंग और खनिजों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है।

मुख्यमंत्री ने 1,368 नव-नियुक्त शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में नव-नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान बांटे। मुख्यमंत्री ने इस चरण में कुल 1,368 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 1,015 टीजीटी, 236 पीजीटी और 117 सॉफ्ट शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि दिल्ली के लाखों बच्चों और उनके परिवारों के साथ बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सुद, शिक्षा निदेशालय के



वरिष्ठ अधिकारीगण सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नए शिक्षकों का जुड़ना दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए बेहतर अकादमिक

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली भाजपा ने पांच जिलों में निकाली तिरंगा यात्रा

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश भाजपा ने पांच जिलों में बृहस्पतिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। बाहरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, करोलबाग, केशवपुरम और शाहदरा जिलों में आयोजित यात्राओं में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने का आह्वान किया गया। बाहरी दिल्ली में सांसद योगेंद्र चांदेलिया के नेतृत्व में रोहिणी सेक्टर-2 से बालेश्वर मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें प्रदेश भाजपा की सह प्रभारी एवं सांसद डॉ. अल्का गुर्जर, विधायक राजकुमार चौहान, मनोज शोकीन और गजेन्द्र दाराल समेत हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में यमुना विहार स्थित जिला कार्यालय से घौडा चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मनोज तिवारी ने कहा कि तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के राष्ट्र समर्पण का प्रतीक है।

दिल्ली विधानसभा 14 और 15 अगस्त को आम लोगों के लिए खुलेगी, सुरक्षा बलों के बैंड की होगी संगीतमय प्रस्तुति

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का भवन व परिसर देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। नागरिक इन दोनों दिनों में शाम 5:00 बजे से सात 8:00 बजे तक विधानसभा परिसर में प्रवेश कर इसके गौरवशाली इतिहास, विरासत और लोकतांत्रिक परंपराओं से परिचित हो सकेंगे। इसके लिए किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए प्रत्येक आगंतुक को आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह

के दौरान इतिहास, संस्कृति और जनभागीदारी का विशेष संगम देखने को मिलेगा। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) बैंड एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) बैंड देशभक्ति से ओत-प्रोत संगीतमय प्रस्तुतियां देंगे। वहीं साहित्य कला परिषद द्वारा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। समारोह के अवसर पर ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा भवन को शाम के समय तिरंगे की रोशनी से विशेष रूप से सजाया और प्रकाशित किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधानसभा



कि तकनीक का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए करना सही है। उन्होंने विद्यार्थियों को याद दिलाया कि सरकार उन्हें ईज ऑफ लर्निंग उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समाज के प्रति उनकी अंतिम जिम्मेदारी अपने ज्ञान और प्रतिभा के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का निर्माण करना है। शिक्षा मंत्री ने युवाओं से कहा कि एआई का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से ही करें। जानें कि यह कैसे काम करता है। लेकिन अपनी सोच को किसी एल्गोरिदम के हवाले न करें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का

निर्माण केवल जीडीपी के आंकड़ से नहीं होगा। भारत 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा और आज की युवा पीढ़ी ही उस भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनु सिंह लाठर ने कहा कि दीक्षार्थ विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत है, जो आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मकता, अंतर्विषयक अध्ययन और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित है।

सहयोग, मार्गदर्शन और नए अवसरों का विस्तार है। यह भर्ती अभियान सरकारी विद्यालयों में रिक पदों को भरने और शिक्षण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विद्यालयों की इमारतों तैयार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी है कि हर कक्षा में योग्य और समर्पित शिक्षक हों, शिक्षण का स्तर बेहतर हो, आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग हो, बच्चों को खेल और कला के पर्याप्त अवसर मिलें। प्रत्येक बच्चा वास्तव में सीखने और आगे बढ़ने में सक्षम हो। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को केवल परीक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से आगे ले जाकर बच्चों के सर्वांगीण विकास से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने नव-नियुक्त शिक्षकों

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ अभाविप का देशव्यापी प्रदर्शन

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

नई दिल्ली। जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों की सीबीआई जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने गुरुवार को देशभर में प्रदर्शन किया। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, सूरत, गोरखपुर, जोधपुर, कोटा, रायपुर, भुवनेश्वर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई शहरों एवं विश्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में वसंत विहार स्थित झारखंड भवन के बाहर अभाविप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए झारखंड सरकार से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जेएसएससी सीजीएल सहित उन परीक्षाओं को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की, जिसकी शुचिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। अभाविप का आरोप है कि

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर झारखंड एवं विद्यार्थी पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। सगठन के अनुसार, 10 और 11 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, वॉटर कैनन के इस्तेमाल और गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अभाविप ने जांच के लिए गठित एसआईटी में बार-बार बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरिय सीबीआई जांच की मांग की। सगठन ने कहा कि अनियमितताओं में दोषी पाए जाने वाले लोगों के साथ-

साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं की अनियमितताओं की निष्पक्ष सीबीआई जांच काराई जानी चाहिए। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल समेत संरक्षक परीक्षाओं को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने तथा परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संस्थागत सुधार की मांग की। राष्ट्रीय मंत्री आदित्य तकिवार ने कहा कि झारखंड के विद्यार्थी अपने भविष्य और न्यायसंगत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं, संस्थाओं और उन संवैधानिक मूल्यों से जोड़ना है, जिन्होंने देश की लोकतांत्रिक यात्रा को दिशा प्रदान की है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीएसएफ एवं सीआरपीएफ बैंड की देशभक्ति से परिपूर्ण प्रस्तुतियां तथा साहित्य कला परिषद के सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह में विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। इनके माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भारत की ऐतिहासिक विधानसभा भवन तथा परिसर में स्थित महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को देखने और दिल्ली के विधायी एवं लोकतांत्रिक इतिहास में विधानसभा की भूमिका को समझने का अवसर

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

न देश के 500+ शहरों में 1.8 लाख से अधिक रेस्टोरेंट पार्टर्स के नेटवर्क के साथ अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, जो किफायती फूड डिलीवरी में सबसे व्यापक पार्टनर नेटवर्कों में से एक है। 99 स्टोर का स्वर्गी फूड ऐप के भीतर एक समर्पित सेक्शन है जो 49, 79 और 99 के ग्राहक चार्टर पर भाग लेने वाले ब्रांडों से दैनिक उपभोग के लिए क्यूरेटेड, किफायती फूड आइटम और भोजन दिखाता है और 49 से ऊपर के ऑर्डर के लिए फ्री डिलीवरी अमल करती है। यह उन वैल्यू-कॉन्सियस ग्राहकों की जरूरतों

स्विगी फूड का अब हर 7 में से 1 ऑर्डर हो रहा 99 स्टोर से, किफायत बनी सबसे बड़ी वजह

नई दिल्ली, प्रातः किरण संवाददाता

राष्ट्रीय। भारत के प्रमुख ऑन-डिमांड सुविधा प्लेटफॉर्म, स्वर्गी लिमिटेड (एनएसई: SWIGGY/बीएसई: 5442285) ने आज घोषणा की कि उसने पिछले एक साल में अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट की अपनी पेशकश 99 स्टोर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया 99 स्टोर अब प्लेटफॉर्म के हर 7 में से 1 फूड ऑर्डर का हिस्सा है, जो वैल्यू-ड्रिवन फूड विकल्पों की मजबूत मांग को दर्शाता है। इस पेशकश

को पुरा करता है जो किफायती कीमत पर विवशनीय ब्रांडों के गुणवत्तापूर्ण फूड और भोजन विकल्पों की तलाश में हैं। पिछले एक साल में, यह स्वस्थ भोजन विकल्पों के लिए भी एक पसंदीदा प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। 99 स्टोर न केवल ऑर्डर की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि नए शहरों में अपना विस्तार कर रहा है, नए रेस्टोरेंट पार्टनर जोड़ रहा है, विनियम से नए यूजर्स को जोड़ रहा है और ग्राहकों को बनाए रखने की क्षमता को बेहतर बना रहा है – यह सब एक ही वैल्यू प्रोपोज़िशन पर हो रहा है।

कपिल देव ने कहा, “भारतीय टीमों को स्पिन के खिलाफ संघर्ष इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि शीर्ष खिलाड़ी पर्याप्त गेंदें क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहीं पर बीसीसीआर को सख्ती दिखानी चाहिए और सभी के लिए मल्टी-डे मैच खेलना अनिवार्य करना चाहिए। इसका एक और पहलु यह है कि युवा पीढ़ी को शीर्ष खिलाड़ियों से सीखने का मौका मिलेगा।” कपिल देव ने कहा, “हाल के समय में स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है।

स्मार्ट ग्रिड पर 1,135 करोड़ खर्च, योजना अधूरी

बादशाहपुर, एजेंसी। साइबर सिटी में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी तस्वीर चिंता बढ़ाने वाली है। सेक्टरों में बिजली के खंभों पर तारों का जाल बना हुआ है। कई जगह मीटर और केबल बेतरतीब तरीके से लटक रहे हैं। वर्षा के दौरान इनसे हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।

शहर में बिजली के खंभे पर बड़ी संख्या में तार लटकते दिखाई दे रहे हैं। कई मीटर खंभे पर एक के ऊपर एक लगाए गए हैं। तार नीचे तक झूल रहे हैं। खंभे के आसपास पानी भरा हुआ है। ऐसे में करंट उतरने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।

दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सेक्टर-1 से 57 तक के 580 फीडों को भूमिगत कर स्मार्ट बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए अलग-अलग कंपनियों को काम दिया गया। 29 सितंबर 2017 को विद्या टेलीलिक को 148 फीडर का काम 255.80 करोड़ रुपये में दिया गया।

टाटा प्रोजेक्ट को 147 फीडर का काम 239.52 करोड़ रुपये में मिला। इसके बाद 28 नवंबर 2018 को टाटा प्रोजेक्ट को 166 फीडर का काम 354.86 करोड़ रुपये में दिया गया। 11 सितंबर 2019 को एलएंडटी को 119 फीडर का काम 285.50 करोड़ रुपये में मिला। इन चार टेंडरों की राशि 1,135.68



करोड़ रुपये है। पूरे स्मार्ट ग्रिड कार्यक्रम पर करीब 1,300 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है। नियम के अनुसार कंपनियों को दो साल में काम पूरा करना था। विद्या टेलीलिक और एलएंडटी के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। लेकिन टाटा प्रोजेक्ट के दोनों काम अभी तक अधूरे हैं। टीएसजीपी-8 में 166 फीडर तैयार किए जाने थे। इनमें 117 फीडर ही तैयार हो पाए हैं।

623 किलोमीटर केबल भूमिगत की जानी थी।

इसमें 546 किलोमीटर केबल ही डाली गई है। 239.52 करोड़ रुपये वाले टीएसजीपी-6 में 147 फीडर तैयार करने थे। इनमें 133 फीडर तैयार हो चुके हैं। 129 फीडर चालू भी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में खुले तार और अव्यवस्थित बिजली ढांचा सवाल खड़े कर रहा है। स्मार्ट ग्रिड के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद बिजली व्यवस्था पटरी पर नहीं है। हमारे आसपास खंभों

पर तारों का जाल है। बारिश में पानी भरने के बाद डर बना रहता है। बिजली निगम को पहले खतरनाक जगहों को चिह्नित कर तार व्यवस्थित करने चाहिए। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। मेरे हिसाब से इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी अगर बिजली के तार इसी तरह लटकते रहें तो यह गंभीर लापरवाही है। स्मार्ट ग्रिड का फायदा लोगों को दिखाई देना चाहिए। केवल कागजों में काम पूरा होना पर्याप्त नहीं है। निगम को अधूरे काम की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ट्रांसफार्मर की अर्थिंग नहीं है। कोई पार्क के किनारे लगा दिया। किसी ट्रांसफार्मर को कवर कर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। भूमिगत केबल डालने की योजना बनाई गई थी तो अभी कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो सकी। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी खंभों पर तारों का बोझ है। बारिश के दिनों में हादसे की आशंका रहती है। स्मार्ट ग्रिड के काम की सार्वजनिक रूप से प्रगति रिपोर्ट जारी की जाए। किस कंपनी ने कितना काम किया और कितना पैसा खर्च हुआ, इसकी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। अधूरे काम को जल्द पूरा कराया जाए और खुले तारों को सुरक्षित किया जाए। आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ न किया जाए। 239.52 करोड़ रुपये 2017 में टाटा प्रोजेक्ट को 147 फीडर स्मार्ट बनाने का टेंडर 354.86 करोड़ रुपये 2018 में टाटा प्रोजेक्ट को 166 फीडर भूमिगत करने का टेंडर।

संक्षिप्त समाचार

राशनकार्डसेपैनतक... मृतक की उम्र साबित करनेके लिए अब 5 कागजात होंगे मान्य



लखनऊ, एजेंसी। राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ लेने के लिए शासन ने अब शहरी क्षेत्र

के आवेदकों के लिए बड़ी सहूलियत दिए जाने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों को अब मृतक की उम्र साबित करने के लिए परिवार / कुटुंब रजिस्टर और हाईस्कूल प्रमाणपत्र न होने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। शासन ने पांच अन्य दस्तावेजों को भी आयु प्रमाण के रूप में मान्य कर दिया है। इनमें राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। उन्होंने कहा है 25 अक्टूबर 2024 को जारी शासनादेश में योजना के लिए मृतक की आयु के प्रमाण के तौर पर परिवार/कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति व जन्मतिथि ऑफिश शैक्षिक प्रमाणपत्र को मान्य किया गया था। मगर नगरीय क्षेत्रों में सामान्य तौर पर परिवार / कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण आवेदकों को आवेदन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसे में शासन ने लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था में बदलाव किया है। चांड व नगरीय क्षेत्र के ऐसे आवेदक, जिनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र नहीं है और परिवार रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। वे निर्धारित पांच दस्तावेजों में से किसी के जरिए मृतक की आयु का सत्यापन करा सकेंगे। आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा भी देनी होगी कि उसके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और संबंधित नगरीय क्षेत्र में परिवार/ कुटुंब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। समाज कल्याण अधिकारी अंजनी कुमार का कहना है कि यह सुविधा केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए लागू होगी।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में 940 गांवों पर भूस्खलन का मंडराता खतरा

देहरादून, एजेंसी। टिहरी गढ़वाल में 940 गांव भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील हैं। वहीं, 06 गांवों को अतिसंवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है। यह बात यूनिवर्सिटी आफ गौर बंगा (बंगाल), विद्यासागर यूनिवर्सिटी (बंगाल) और यूनिवर्सिटी आफ टेनोन्गला (आस्ट्रेलिया) के संयुक्त अध्ययन में सामने आई। जिसे स्पेशियल इंफार्मेशन रिसर्च में 23 जून 2026 को प्रकाशित किया गया। भूस्खलन के लिहाज से गांवों को संवेदनशीलता के अध्ययन के लिए विज्ञानियों ने 1,600 पुराने भूस्खलन स्थानों और उन्हें प्रभावित करने वाले 17 भौगोलिक, जलवायु, मिट्टी, भूगर्भीय और मानवीय कारकों को मिलाकर पांच मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल से संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किए। अध्ययन में टिहरी के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों को अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील पाया गया, जबकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संवेदनशीलता काफी कम रही। शोधकर्ताओं ने 31 दिसंबर 2004 से 11 नवंबर 2022 के बीच उपलब्ध गूगल अर्थ चित्रों, पूर्व प्रकाशित अध्ययनों, सरकारी रिपोर्ट, समाचार रिपोर्ट और मैदानी सर्वेक्षणों से 1,600 भूस्खलन स्थान दर्ज किए। इन स्थानों का जीपीएस और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऐतिहासिक आंकड़ों से भी सत्यापन किया गया। इनमें ढलान, ऊंचाई, ढलान की दिशा, घरातल की वक्रता, स्थलाकृतिक आर्द्रता सूचकांक, स्थलाकृतिक स्थिति सूचकांक, वार्षिक वर्षा, जलधारा शक्ति सूचकांक, नदी से दूरी, मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की बनावट, मिट्टी की गहराई, भूविज्ञान, भूगर्भीय रेखाओं का घनत्व, भूमि उपयोग-भूमि आवरण, सड़क से दूरी और वनस्पति सूचकांक शामिल हैं।

जयपुर में खुली जेल के कैदी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद बदमाश फरार

जयपुर, एजेंसी। करणी विहार क्षेत्र में खुली जेल के कैदी गंगासहाय कुमावत (40) की बुधवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने कुमावत पर तीन राउंड फायरिंग की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। जांच में सामने आया कि मृतक ने वर्ष 2018 में शहर में महेंद्र नामक व्यक्ति की हत्या की थी। उसी मामले में वह सजा काट रहा था। करीब आठ वर्ष तक जेल में रहने के बाद उसके सही व्यवहार को देखते हुए करीब तीन माह पहले खुली जेल में स्थानांतरित किया गया था। वहां रहते हुए कुमावत दिन में रोजगार के सिलसिले में प्रतिदिन बाहर जाता था। शाम को उसे लौटना होता था। अन्य दिनों की तरह कुमावत बुधवार शाम जेल लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए नाकेबंदी करवाई गई है। वहीं, राज्य के टोंक जिला मुख्यालय पर स्थित जेल में बंद एक कैदी की तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई। मृतक कैदी गणदेव गुर्जर सवाईमाधोपुर का निवासी था। गणदेव की मौत के बाद स्वजन ने जेल के मुख्याद्वार के बाहर हंगामा किया।

खतरे में जेलोंस्की की कुर्सी? पुतिन के करीबी सर्बिया को साधने में जुटे यूक्रेनी राष्ट्रपति

कीव, एजेंसी। रूस के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। हाल ही में जारी हुए सोसिस सर्वे के अनुसार, यदि देश में राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा दौर होता है, तो जेलेंस्की को अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वियों से करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। सर्वे में जेलेंस्की को केवल 33.8वोट मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख वालेरी जालुझनी 66.2वोट समर्थन के साथ काफी आगे चल रहे हैं। इस बढ़ते खेरेलू राजनीतिक दबाव के बीच जेलेंस्की को एक तरफ युद्ध के मोर्चे पर रूस का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है।

सर्बिया के साथ कूटनीतिक संतुलन की कोशिश—आंतरिक राजनीतिक संकट के बीच जेलेंस्की ने सर्बिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की है। यूरोप में सर्बिया को रूस का सबसे बड़ा हिमायती माना जाता है। इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुचिच के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग पुतिन का समर्थक है। सर्बिया ने रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का भी साथ नहीं दिया है। इसके बावजूद जेलेंस्की का दौरा बेहद रणनीतिक है, क्योंकि यूक्रेन को युद्ध जारी रखने के लिए भारी मात्रा में गोला-बारूद और हथियारों की आवश्यकता है, जिसे सर्बिया का रक्षा उद्योग पूरा कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यूआई के निवेश से यूक्रेन और सर्बिया मिलकर एक संयुक्त ड्रोन फैक्ट्री बनाने पर भी विचार कर रहे हैं।

रूसी मिसाइलों ने मचाया कहर— सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है, जहां रूस के ताबड़तोड़ हमलों के कारण यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ता दिख रहा है। रूस ने अकेले जुलाई के महीने में रिकॉर्ड 126 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जो युद्ध के दौरान किसी एक महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 15 अगस्त को कीव पर हुए हमले में रूस ने 24 बैलिस्टिक और 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागीं, जिससे भारी तबाही हुई। इसके अलावा, कीव और आसपास के इलाकों में हुए हालिया हमलों में एक बच्चे सहित चार लोगों की मौत हो गई। हालांकि, यूक्रेनी वायु सेना ने 151 में से 135 रूसी ड्रोनो को मार गिराया, लेकिन पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी के कारण यूक्रेन के महत्वपूर्ण टिकाने अब भी रूसी हमलों के सामने असुरक्षित बने हुए हैं। रूस के लगातार होते हमलों के जवाब में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदलते हुए लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे रूस के विशाल भौगोलिक फैलाव की कमजोरी उजागर हो रही है।

मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, 'ईरान पर भरोसा करने वाला मैं आखिरी व्यक्ति हूं। उन्होंने लगातार मुझसे झूठ बोला है।' ट्रंप ने कहा कि इस समय हेर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरी तरह नियंत्रण है। उन्होंने कहा, उनका (ईरान) नियंत्रण नहीं है। हमारा पूरा नियंत्रण है। यह हमारे कब्जे में है। ट्रंप ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी समय ईरान ने कुछ करने की कोशिश की, तो उसे 'उड़ा दिया' जा सकता है। उन्होंने कहा, 'अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं।'

एक अन्य बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी सुरक्षा को लेकर कहा कि वह सीक्रेट सर्विस और सेना के निर्देशों का पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी तरह सीक्रेट सर्विस पर निर्भर करता है और वह

वही करते हैं जो सीक्रेट सर्विस उनसे करने के लिए कहती है।

ट्रंप ने बताया कि सीक्रेट सर्विस ने उन्हें एक अलग उड़ान और अलग विमान से



जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वह विमान भी उतना ही सुरक्षित था। लेकिन सीक्रेट सर्विस चाहती थी कि वह उसी

विमान से यात्रा करें, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। ट्रंप ने कहा, मैं वही करता हूं जो वे कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शाब्द वहां कोई खतरा था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें बहुत सारी धमकियां मिलती रहती हैं।

तुर्किये में पिछले महीने नाटो सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से गंभीर खतरे के चलते बेहद गोपनीय तरीके से वहां से निकाला गया था। ट्रंप को एयरफोर्स वन के पुराने विमान से एक खानापान सामग्री ले जाने वाले कटेनर के जरिये निकालकर दूसरे सैन्य विमान तक पहुंचाया गया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह 8 जुलाई को पुराने एयरफोर्स वन से ब्रिटेन जाएंगे। पत्रकारों ने तुर्किये में ट्रंप को पुराने नीले रंग के 747 विमान में चढ़ते हुए भी देखा था। हालांकि, ट्रंप उस विमान में सवार नहीं हुए। उन्हें दूसरी तरफ से कटेनर के जरिये निकालकर एक सी-32ए सैन्य विमान से गुप्त रूप से ब्रिटेन भेजा

गया। गौतलब है कि 747 विमान कतर के शाही परिवार ने अमेरिका को उपहार में दिया था।

अचानक बदला प्लान : ट्रंप एक माह पहले कतर के शाही परिवार से उपहार में दिए गए इस विमान से तुर्किये पहुंचे थे। उन्हें इसी विमान से ब्रिटेन जाना था लेकिन ऐन वक्त पर प्लान बदला गया और कटेनर में बैठकर सी-32ए सैन्य विमान तक पहुंचाया गया।

तीसरी बार चुनाव लड़ने के सवाल पर क्या कहा

ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल को टालते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन कानून इस मामले में बहुत सख्त है। ट्रंप ने कहा, हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन कानून बहुत सख्त है।

राजस्थान के मंत्री ने ही अपनी सरकार के खिलाफ दिया धरना, जिला कलेक्टर वनिगम आयुक्त को बताया भ्रष्टाचारी

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान सरकार के वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ समर्थकों के साथ धरना दिया। अलवर नगर निगम में मंत्री ने पांच घंटे तक अधिकारियों के खिलाफ धरना देते हुए जिला कलेक्टर अतिका शुक्ला और निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम जनता की सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर धरना देते हुए मंत्री ने कलेक्टर को लूटकर खाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त के टालमटोल रवैये के कारण चर्यानि 329 अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि निगम में सफाई कर्मचारियों का करीब छह महीने पहले चयन हो गया था, लेकिन कलेक्टर और निगम आयुक्त सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने के काम में देरी कर रहे थे। मंत्री ने इस संबंध में कलेक्टर पर निगम आयुक्त से पूर्व में कई बार बातचीत की, लेकिन वे इस काम को टाल रहे थे। इससे नाराज होकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ धरना दिया। मंत्री के साथ कांग्रेस के दो नेता भी धरने पर बैठ गए। मंत्री के धरना देने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटोसरा और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राज्य सरकार को घेरा।

बेंगलुरु में बदहाल सड़क बनी जानलेवा, ब्रेक लगाते ही बाइक से गिरी महिला को मिनी ट्रक ने कुचला

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के पास अनंतनगर मेन रोड पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खराब सड़क के कारण ब्रेक लगने से दोपहिया वाहन फिसल गई, इस दौरान बाइक पर पीछे बैठी 32 वर्षीय महिला मेधा गिर गई।

इस दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक मिनी मालवाहक वाहन ने महिला को कुचल दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महिला मेधा को मृत घोषित कर दिया। दरअसल, श्रद्धा कार्यालय में कार्यरत मेधा अपने सहकर्मी के साथ दोपहिया वाहन पर सिंगासद्रा की ओर जा रही थी, इसी दौरान कीचड़ भरे टूटी सड़क पर एक पैदल यात्री को बचाने के लिए कार और बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगाए।

ब्रेक लगते ही मेधा बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद उसे एक मिनी ट्रक ने कुचल दिया और मेधा की मौत



हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

पीड़िता मेधा आकर्ष अनंतनगर की निवासी और मूल रूप से केरल की रहने वाली थी। वह कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कार्यालय में काम करती थी।



उसके परिवार में उसका पति आकर्ष और तीन वर्षीय बेटा है। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना अनंतनगर मेन रोड पर सुबह करीब 9 बजे हुई, जब मेधा अपने एक सहकर्मी अजय गुरु के साथ अनंतनगर से सिंगासद्रा की ओर जा रही थीं। इस घटना

से स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया, स्थानीय निवासियों ने सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश जताया और इस दुर्घटना के लिए सड़क की खराब स्थिति को जिम्मेदार ठहराया। एक स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित संदेश में कहा गया, 'इस मौत के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सड़कें बुरी तरह से जर्जर होने के कारण कीचड़ और दलदल से भरी हुई हैं।' 'पुलिस ने सड़क की खराब स्थिति को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जांच में अचानक ब्रेक लगाने की दुर्घटना का तात्कालिक कारण बताया गया है। पुलिस ने बताया कि वह मौजूद किसी भी व्यक्ति ने मिनी मालवाहक वाहन का नंबर नोट नहीं किया। हम आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रहे हैं।

अमेरिका की वीजा नीति का असर: घट सकते हैं 1.1 लाख विदेशी छात्र, होगा 3.4 अरब डॉलर का नुकसान; रिपोर्ट में दावा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की सख्त वीजा नीति और बदलती नीतियों को लेकर बनी अनिश्चितता का असर विदेशी छात्रों के दाखिले पर पड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के शीतकालीन सत्र में अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले में 1.1 लाख तक की कमी आ सकती है। शिक्षकों के संगठन (एनएएफएसए) एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स और शोध संस्था जेबी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी छात्रों की संख्या घटने से अमेरिकी स्थानीय अर्थव्यवस्था को 3.4 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 32,457.83 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। इससे करीब 39,000 नौकरियों पर भी असर पड़ने का अनुमान है।

11.69 लाख से घटकर 10.57 लाख हो सकती है संख्या

रिपोर्ट के अनुसार, 2025-26 के शीतकालीन सत्र में अमेरिका में विदेशी छात्रों के दाखिले की अनुमानित संख्या 11.69 लाख थी। इस साल यह घटकर 10.57 लाख रह सकती है। अमेरिका में विदेशी छात्रों के सबसे बड़े स्रोत के तौर पर भारत की अहम भूमिका है। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष में 3.63 लाख से अधिक भारतीय छात्रों ने अमेरिका में अलग-अलग पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025-26 के शीतकालीन सत्र में विदेशी छात्रों ने अमेरिकी स्थानीय अर्थव्यवस्था में 41.77 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 3,98,754.02 करोड़ रुपये) का योगदान दिया था। 2026-27 में यह

घटकर 38.37 अरब डॉलर (करीब 3,66,296.19 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है। एनएएफएसए की कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फैटा आव ने कहा कि अमेरिका की नीतियां और नियम इस बात को प्रभावित करते हैं कि विदेशी छात्र अपना भविष्य



कहां बनाने का फैसला करते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के ये फैसले अमेरिकी समाज और अर्थव्यवस्था पर छोटे और लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं।

विश्व कप टिकट धारकों को वीजा प्राथमिकता भी बनी वजह

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सख्त वीजा नीतियों के अलावा, विदेश विभाग की ओर से फीफा विश्व कप के टिकट धारकों को

छात्रों की तुलना में वीजा जारी करने में प्राथमिकता देना भी विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों के दाखिले को प्रभावित कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से इस व्यस्त मौसम में विदेश विभाग छात्र और शोधकर्ता वीजा आवेदनों को प्राथमिकता देता रहा है। इससे छात्रों को समय पर विश्वविद्यालय परिसरों में पहुंचने में मदद मिलती थी।

कई देशों के यात्रियों पर पहले भी लगी थी पाबंदी

पिछले साल अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अफगानिस्तान और यमन समेत दर्जनों देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा, पिछले महीने अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एक नियम को अंतिम रूप दिया। इसके तहत विदेशी छात्रों को विस्तार की मंजूरी के बिना अमेरिका में चार साल से अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं होगी। इस बदलाव से लंबे समय वाले डॉक्टरेट कार्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उन छात्रों पर भी असर पड़ सकता है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अस्थायी तौर पर अमेरिका में काम करने की उम्मीद रखते हैं।

ईरानी मिसाइल के निशाने पर थे ट्रंप: दावा- आईआरजीसी को पता थी लोकेशन, खुफिया एजेंसियों ने कैसे फेरा मंसूबे पर पानी

वॉशिंगटन, एजेंसी। नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर खतरे का दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कई इन्पुट मिले थे कि ईरान को तुर्किये की राजधानी अंकारा में ट्रंप के ठिकाने की सटीक जानकारी थी। बताया गया कि ईरानी एजेंटों को उस होटल की मॉजिल तक की जानकारी थी, जहां ट्रंप ठहर रहे हुए थे। सुरक्षा अधिकारियों ने इसी दौरान ट्रंप को निशाना बनाने वाले संभावित सहज से हवा में मार करने वाले मिसाइल खतरे का भी पता लगाया। खतरे का आकलन इतना गंभीर बताया गया कि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने असाधारण सुरक्षा योजना तैयार की। रिपोर्ट के मुताबिक, नाटो सम्मेलन के आसपास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ भी देखा गया था। साथ ही ऐसी जानकारी सामने आई कि ट्रंप को ले जाने वाले विमान को निशाना बनाया जा सकता है। इसके बाद ट्रंप की आवाजाही को सार्वजनिक रूप से सामान्य दिखाते हुए उन्हें गुप्त तरीके से दूसरे विमान में भेजने की योजना बनाई गई।